देशहित संदेश

हर पन्ना जो बदले आपकी तकदीर

वर्ष-14, अंक-81, बुधवार, 01 अप्रैल 2026, पृष्ठ-08, मूल्य- ₹ 2.00 E-mail :- deshhitsandesh@gmail.com

भाजपा ने खोला आप का पिंक कार्ड वाला भ्रम जाल...

पेज 03

संक्षिप्त खबरें

भारत बना नागोया प्रोटोकॉल में नंबर-1

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। जैव विविधता संरक्षण और संसाधनों के निष्पक्ष उपयोग के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आइआरसीसी) जारी करने में भारत दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। एबीएस क्लियरिंग-हाउस के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर में जारी कुल 6,311 प्रमाणपत्रों में से 3,561 प्रमाणपत्र अकेले भारत ने जारी किए हैं, जो कुल का 56 प्रतिशत से अधिक है। इस मामले में भारत अन्य देशों से काफी आगे है। भारत के बाद फ्रांस (964), स्पेन (320), अर्जेंटीना (257), पनामा (156) और केन्या (144) का स्थान है। नागोया प्रोटोकॉल के तहत आइआरसीसी एक आधिकारिक प्रमाण होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी देश के आनुवंशिक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से पहले अनुमति ली गई है और लाभ साझा करने की शर्तें तय हैं। भारत की इस उपलब्धि के पीछे जैव विविधता अधिनियम, 2002 और मजबूत संस्थागत ढांचा है। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर काम कर रही एजेंसियों ने इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाया है। यह उपलब्धि दिखाती है कि भारत न सिर्फ जैव विविधता संरक्षण में अग्रणी है, बल्कि संसाधनों के निष्पक्ष उपयोग और लाभ के समान वितरण के लिए भी प्रतिबद्ध है।

नौसेना को मिला 'सर्वेक्षण', चार सर्वे पोतों की परियोजना पूरी

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना को चौथा और अंतिम सर्वेक्षण पोत (विशाल) ह्यसंशोधकह्न सौंप दिया गया है। इसके साथ ही चार बड़े सर्वेक्षण पोतों की परियोजना पूरी हो गई है, जो देश की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस अत्याधुनिक पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) में किया गया। 30 मार्च 2026 को इसे औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इस परियोजना के तहत पहले तीन पोत- आईएनएस संधायक (फरवरी 2024), आईएनएस निर्देशक (दिसंबर 2024) और आईएनएस इक्षक (नवंबर 2025) पहले ही नौसेना में शामिल किए जा चुके हैं। अब 'संशोधक' के शामिल होने से यह परियोजना पूरी हो गई है। 'संशोधक' अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने में सक्षम है। यह पोत तटीय और गहरे समुद्र दोनों क्षेत्रों में सर्वे कर सकता है और नौवहन मार्गों के निर्धारण में मदद करेगा।

ग्रीन अमोनिया समझौते से ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती: नड्डा

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में स्वच्छ ऊर्जा और उर्वरक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ग्रीन अमोनिया से जुड़े अहम समझौते किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इसे सस्टेनेबल फर्टिलाइजर उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत उर्वरक कंपनियों और ग्रीन अमोनिया उत्पादकों के बीच 11 परियोजनाओं के लिए खरीद और आपूर्ति समझौते किए गए हैं। इन समझौतों से देश में ग्रीन अमोनिया की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

भारत में उर्वरक उत्पादन का बड़ा हिस्सा आयातित अमोनिया पर निर्भर है। इस पहल से आयात पर निर्भरता घटेगी, कीमतों में स्थिरता आएगी और अगले 10 वर्षों में लगभग 2.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचत होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का है। ग्रीन अमोनिया को बढ़ावा देने से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि उर्वरक क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।

होर्मुज के रास्ते नहीं मिल रहा तो अमेरिका से खरीदें तेल: ट्रंप

वाशिंगटन, आईएएनएस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक प्रस्ताव रखा है। मंगलवार को ट्रुथ पोस्ट में उन्होंने जेट ईंधन की कमी से जूझ रहे देशों से कहा की कि अगर होर्मुज से तेल नहीं मिल पा रहा तो अमेरिका का रुख कर सकते हैं। दो अलग-अलग पोस्ट्स में उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन को जबरदस्त फटकार भी लगाई है।

ट्रंप ने तेल को लेकर कहा, ब्रिटेन जैसे देश (जिसने ईरान को सत्ताच्युत करने की कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था) और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए जेट फ्यूल नहीं हासिल कर पा रहे हैं, उनको मैं दो नसीहत दूंगा। इसके बाद ट्रंप ने वो दो नसीहतें देते हैं। उन्होंने आगे लिखा, पहली, चाहूंगा कि उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त तेल है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दूसरी नसीहत हौसला और हिम्मत दिखाने की कही। लिखा कि मेरी दूसरी सलाह है कि देर से ही सही लेकिन थोड़ी हिम्मत दिखाएं, होर्मुज जाएं और अपना हक ले लें। ट्रंप आगे लिखते हैं कि आपको खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। दावा किया कि हमेशा अमेरिका उनका साथ देने के लिए मौजूद नहीं रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे आप उसके साथ खड़े नहीं हैं। दुनिया को ललकारते और अपनी पीठ थपथपाते हुए ट्रंप ने अंत में लिखा, ईरान कमजोर हो चुका है, वो तबाह कर दिया गया है। सबसे मुश्किल काम हमने कर दिया है। अब आप जाकर अपना तेल हासिल करने का हौसला दिखाना चाहिए।

इसकी अगली पोस्ट में ट्रंप ने फ्रांस को फटकार लगाई है। नाराजगी जाहिर करते हुए उसे कोसा है। लिखा- फ्रांस ने इजरायल जा रहे उन विमानों को अपने इलाके के ऊपर से उड़ने नहीं दिया, जो सैन्य सामान से लदे हुए थे। ₹ईरान के कसाई₹ को खत्म करने के मामले में फ्रांस बिल्कुल भी मददगार साबित नहीं हुआ, जिसे आखिरकार हमने मार गिराया और इस रवैए को अमेरिका याद रखेगा! ट्रंप ने उन यूरोपीय सहयोगियों के प्रति अपनी नाराजगी लगातार जाहिर की है, जिन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य अभियान में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है— खास तौर पर तब, जब उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए फिर से खोलने के बेहद खतरनाक प्रयासों में शामिल होने को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त की थीं।

'हॉर्मूज' के बाद अब 'बाब-अल-मंदेब' पर भी संकट गहराने की आशंका, इंडियन नेवी अलर्ट

ईरान का इजरायल और अमेरिका के साथ संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। हूतियों ने इजरायल पर कई मिसाइल हमले किए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाधित होने के चलते वैश्विक ऊर्जा संकट पहले ही गहरा चुका है। अब एक और खतरा स्ट्रेट ऑफ बाब-अल-मंदेब पर मंडरा रहा है, जो रेड सी और अदन की खाड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण चोक प्वाइंट है। इसी कारण भारतीय नौसेना पूरी तरह सतर्क है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस समय उत्तरी अरब सागर में ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी के आसपास भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत तैनात हैं। एंटी-पायरेसी मिशन के तहत यहां हमेशा एक युद्धपोत मौजूद रहता है। वेस्ट एशिया संकट के दौरान भारतीय नौसेना लगातार भारतीय कच्चे तेल और एलपीजी टैंकरों को एस्कॉर्ट कर रही है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक आवश्यकता पड़ने पर यहां भी भारतीय ध्वज वाले जहाजों को अतिरिक्त सुरक्षा भी दी जा सकती है।

अमेरिका- इजरायल नहीं चाहते ईरान और अरब देशों के बीच संबंध रहें सामान्य: लावरोव

मास्को, आईएएनएस। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का आरोप है कि अमेरिका-इजरायल शांति की इच्छा नहीं रखते हैं। उन्होंने रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल की एक बैठक में दावा किया कि अमेरिका और इजरायल, ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच सामान्य रिश्ते (नॉर्मलाइजेशन) नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका और इजरायल, ईरान और अरब देशों के बीच संबंध सामान्य होने से रोक रहे हैं, और 2010 में रूस की पहल पर किए गए सामूहिक खाड़ी सुरक्षा प्रस्ताव को कमजोर कर रहे हैं। लावरोव ने कहा कि क्षेत्र में चल रहे 'रेजीम चेंज' (तख्तापलट) के पीछे असली मकसद तेल और गैस संसाधनों पर कब्जा हासिल करने की बेताब कोशिश है। लावरोव ने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो यह संकट पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है और एक बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकता है।

छात्र जीवन की यादों में खोये एलजी, कमला नगर में प्रसिद्ध छोले-भटूरे का लिया स्वाद

पार्किंग, सफाई, सुरक्षा और पीजी किराये के मुद्दों का जल्द समाधान का भरोसा

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू अपने छात्र जीवन की यादों को ताजा करने और युवाओं से सीधा संवाद करने के लिए राजधानी के प्रसिद्ध कमला नगर मार्केट पहुंचे।

यहां उन्होंने स्थानीय लोगों, दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों और बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों से बातचीत कर क्षेत्र की जमीनी हकीकत जाना। इसके अलावा नागरिक समस्याओं का फीडबैक लिया।

बाजार की रौनक के बीच लोगों से मुलाकात

एलजी ने कमला नगर की व्यस्त गलियों में पैदल घूमकर बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों, कर्मचारियों, ग्राहकों, पर्यटकों और खासतौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की। बाजार में उनकी मौजूदगी देखकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। कई छात्र-छात्राएं उनके साथ फोटो लेते नजर आए, वहीं एलजी संधू भी सहज अंदाज में लोगों से घुलते-मिलते दिखाई दिए।

'चाचे दी हट्टी' के छोले-भटूरे का लिया स्वाद

एलजी ने कमला नगर की पहचान बन चुके मशहूर 'चाचे दी हट्टी' के छोले-भटूरे का स्वाद लिया। यह दुकान वर्षों से छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच खासा लोकप्रिय रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस अनुभव को साझा करते हुए लिखा कि 'कमला नगर में 'चाचे दी हट्टी' के छोले-भटूरे का स्वाद आज भी उतना ही लाजवाब है, जिसने मेरे पुराने दिनों की यादें ताजा कर दीं।

स्थानीय मुद्दों पर खुलकर हुई चर्चा...दौरे के दौरान छात्रों और स्थानीय लोगों ने कई समस्याएं सामने रखीं। छात्रों ने बताया कि बाजार में पार्किंग की भारी कमी है, जिससे रोजाना जाम की स्थिति बनती है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और कई जगह कचरा जमा रहता है। सुरक्षा को लेकर भी लोगों ने चिंता जताई, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर छात्रों ने अपनी परेशानी साझा की। साथ ही छात्रों ने पीजी (पेइंग गेस्ट) आवास के बढ़ते किराये को बड़ा मुद्दा बताया, जिससे यहां रहना लगातार महंगा होता जा रहा है।

'के-नैग्स' के नाम से भी विख्यात कमला नगर मार्केट में आज भी युवाओं और खरीदारों की वही पुरानी रौनक देखने को मिली। स्थानीय लोगों से बातचीत में पार्किंग, सफाई, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और छात्रों के पीजी किराये जैसी अहम समस्याएं सामने आई हैं। इन सभी मुद्दों को संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ उठाकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के लोगों और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। **उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू**

व्यापारियों की भी अलग चिंता

दुकानदारों और व्यापारियों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। उनका कहना है कि बाजार में अनियंत्रित पार्किंग के कारण ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत होती है। कई बार गाड़ियों की इतनी भीड़ हो जाती है कि दुकानों का फ्रंट ही दिखाई नहीं देता, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है।

छात्रों ने किराये और सुरक्षा पर जताई चिंता

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने विशेष रूप से पीजी के बढ़ते किराये और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते किराये के कारण कई छात्रों को मजबूरन अन्य इलाकों में रहने के विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं।

समयबद्ध समाधान का आश्वासन

एलजी संधू ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इन मुद्दों को संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इनका समाधान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कमला नगर में आने वाले लोगों और यहां रहने वाले छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

सुधार की जरूरत, पहल से उम्मीद...कमला नगर जैसे व्यस्त और लोकप्रिय बाजार में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। एलजी के इस दौरे को स्थानीय समस्याओं के समाधान की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।

भारत में इस साल 4 और अगले वर्ष दो सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार हो जाएंगे : अश्विनी

नई दिल्ली (डीएचएस ब्यूरो)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि 2026 में भारत में चार सेमीकंडक्टर प्लांट के तैयार होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सानंद में केयन्स सेमीकॉन के ओएसएटी प्लांट का उद्घाटन करने के बाद, वैष्णव ने कहा 2026 तक चार सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार हो जाएंगे और 2027 तक दो प्लांट का काम पूरा हो जाएगा। भारत की पहली फैब्रिकेशन यूनिट 2028 तक धोलेरा में तैयार हो जाएगी। उन्होंने बताया कि केयन्स सेमीकॉन की सानंद यूनिट देश का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित देश के सबसे पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन 28 फरवरी को हुआ था और आज, 31 मार्च को, दूसरे प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तीसरे प्लांट का उद्घाटन जुलाई में किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि केयन्स सेमीकॉन की सानंद यूनिट ने मात्र 14 महीनों में नींव से लेकर औद्योगिक उत्पादन का सफर शुरू किया है।

उन्होंने आगे कहा कि यह विकास भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बढ़ती क्षमताओं को दशार्ता है और इसने देश भर के इंजीनियरों और छात्रों को प्रोत्साहित किया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ₹हमें गुणवत्ता और लागत के मामले में जीत हासिल करनी होगी; तभी हम विश्व स्तर पर अपनी स्थिति बनाए रख सकेंगे और मजबूत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मशीनरी, रसायन, गैस और परीक्षण अवसंरचना सहित एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास द्वारा सेमीकंडक्टर कार्यक्रम को समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, ₹लगभग 60,000 युवा इंजीनियरों को सिनॉप्सिस और कैडेंस जैसे विशिष्ट वैश्विक उपकरणों में प्रशिक्षित किया गया है। वैष्णव ने आगे कहा कि 315 विश्वविद्यालयों से आए ये इंजीनियर चिप डिजाइन प्रयासों में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, इन युवा इंजीनियरों द्वारा डिजाइन की गई चिप्स चंडीगढ़ की एक प्रयोगशाला में निर्मित की जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एनवीडिया, एएमडी और इंटेल सहित वैश्विक कंपनियां भारत में उन्नत चिप डिजाइन का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, भारत में बेहद जटिल 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन किए जा रहे हैं, और आगे जोड़ा, 'हमारा दृष्टिकोण है 'डिजाइन इन इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' है। अगले चरण का जिक्र करते हुए वैष्णव ने कहा, सेमीकंडक्टर 2.0 के तहत, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि पूरा इकोसिस्टम - मशीनें, गैसें और रसायन - भारत में उपलब्ध होना चाहिए।

सीजेआई ने लद्दाख के एलजी सक्सेना की कार्यशैली को सराहा

डीएचएस ब्यूरो

लेह/नई दिल्ली भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व और उनके प्रशासनिक कौशल की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की है। एक उच्च स्तरीय न्यायिक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने उपराज्यपाल को एक गतिशील प्रशासक बताया। उन्होंने कहा कि लद्दाख जैसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र में जिस तत्परता के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं, वह देश के अन्य हिस्सों के लिए एक मिसाल है।

सीजेआई सूर्यकांत ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उपराज्यपाल सक्सेना के कार्यकाल में लद्दाख में प्रशासनिक कार्यों की गति में अभूतपूर्व तेजी आई है। सक्सेना केवल एक पद पर आसीन अधिकारी नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी नेता हैं जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में विश्वास रखते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने विशेष रूप से न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार में एलजी के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एलजी प्रशासन ने सराहनीय सक्रियता दिखाई है। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना एक बड़ी चुनौती रही है।

दिल्ली में पिंक कार्ड को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम: सीएम रेखा गुप्ता

बोलीं अफवाह इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि पहले इसके भुगतान का कोई हिसाब नहीं रखा जाता था

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को लिए जारी पिंक कार्ड को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने इसे आम आदमी पार्टी की राजनीतिक साजिश बताया है।

रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक वीडियो संदेश में कहा, दिल्ली की मेरी बहनों, कुछ राजनेता राजनीतिक दुष्प्रचार के जरिए यह झूठा दावा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं के लिए बना पिंक कार्ड तब काम नहीं करता, जब आप एक बस में सफर करें, उसे एक बार टैप करें, उतरें और दूसरी बस में चढ़ें। यह पूरी तरह गलत और झूठा है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आपका पिंक कार्ड बिल्कुल सही काम करता है।

रेखा गुप्ता ने कहा, ये अफवाह इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि डीटीसी की बसों में रोजाना 45 लाख लोग यात्रा करते हैं। इसमें से 20 लाख दिल्ली की बहनें यात्रा करती हैं। इसका भुगतान दिल्ली सरकार करती थी। पहले इस भुगतान का कोई हिसाब नहीं रखा जाता था। बेहिसाब बिल बनाकर लूट की जाती थी।

रेखा गुप्ता ने कहा, पिंक कार्ड का फायदा ये है कि आप जितना भी बार बस में जाएंगी-आएंगी, उसके खर्चे का सही हिसाब-किताब नोट हो जाएगा और उसके लिए जो सरकार को पैसा देना है, वह बिना किसी भ्रष्टाचार के बिना किसी निजी लाभ के दिया जाएगा।

अब जो लोग चाहते हैं कि ये खर्चा बिना बात के किसी निजी व्यक्ति को लाभ मिलता रहे, वो नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को तकलीफ हो रही है। ये पिंक कार्ड अभी आसानी से बन रहे हैं। अगले तीन महीने तक बनते रहेंगे। किसी लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा दिन में कितनी बार भी किसी समय बस में यात्रा करने पर कोई पैसा नहीं लगेगा। दिल्ली की बहनों के साथ आपकी ये मुख्यमंत्री हमेशा रहेगी।

नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़ से नौ की मौत, कई घायल

रत्नेश पाण्डेय

पटना। नालंदा जिले के बिहारशरीफ स्थित शीतला माता मंदिर में मंगलवार की सुबह भारी भीड़ के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में नौ महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताते हुए मुआवजे का एलान किया है।

मंगलवार को विशेष पूजा

चैत्र महीने का अंतिम मंगलवार, सुबह से उमड़ी थी भारी भीड़ चैत माह का अंतिम मंगलवार होने के कारण शीतला माता मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने लगे थे। करीब 9 बजे किसी अफवाह के बाद अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान कई महिलाएं गिर पड़ीं और भीड़ के दबाव में कुचल गईं।

प्रधानमंत्री ने जताया दुःख

नालंदा भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के आश्रितों को 2 लाख मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान

सीएम नीतीश कुमार ने 6 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये आपदा प्रबंधन विभाग से 2 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 6 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। सीएम ने घायलों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया है और वरीय अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है।

राष्ट्रपति के दौरे की तैयारी के बीच मची अफरा-तफरी

मरने वालो में ज्यादातर महिलाए

मरने वालों में कई महिलाएं शामिल हैं, जिनकी पहचान दयावंती देवी, मालो देवी, किरता देवी, रीता देवी, आशा देवी और रेखा देवी के रूप में हुई है। तीन अन्य महिलाओं की पहचान की प्रक्रिया जारी है। घायलों को तुरंत बिहारशरीफ के मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

राष्ट्रपति के नालंदा दौरे की तैयारी में व्यस्त था प्रशासन

घटना के वक्त जिला प्रशासन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के नालंदा दौरे की तैयारियों में व्यस्त था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंदिर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। हादसे के बाद मंदिर परिसर में चीख-पुकार मच गई। कई लोग अपने परिजनों को खोजते नजर आए। विशेषकर महिलाएं और बच्चे काफी देर तक सहमे हुए दिखाई दिए।

प्रत्यक्षदर्शियों ने सुनाया दर्द

'भीड़ बेकाबू थी, कोई संभालने वाला नहीं था' घायल रीता देवी ने भावुक होकर बताया,

'हम चार सहेलियां मंदिर आए थे। अचानक लोग इधर-उधर भागने लगे। मेरी एक सहेली गिर गई और लोग उस पर चढ़ते चले गए...' सोनम कुमारी ने कहा– 'मैं मां को मना कर रही थी कि आगे मत जाओ, भीड़ बहुत है... लेकिन भगदड़ में मां की मौत हो गई।' स्थानीय महिलाओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।

जिला प्रशासन की सफाई

'स्थिति अब नियंत्रण में' नालंदा जिला प्रशासन ने बयान जारी कर कहाः राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। आयुक्त, आईजी, डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है। घटना की जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

आयुक्त और वरीय पदाधिकारी कर रहे हैं राहत और बचाव कार्यों की निगरानी

नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में स्थित मां शीतला मंदिर में भगदड़ के बाद घटनास्थल पर पटना के आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय क्षेत्र, पटना भी पहुंचकर निरीक्षण कर चुके हैं। घटना स्थल पर जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक नालंदा एवं उप विकास आयुक्त स्वयं उपस्थित रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

नालंदा मधड़ा शीतला मंदिर भगदड़ केस में बड़ी कार्रवाई: चौकीदार के ह्वाले थी सुरक्षा

नालंदा के मधड़ा स्थित शीतला मंदिर में हुई दर्दनाक भगदड़ घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही उजागर होने के बाद दीपनगर थाना के थानाध्यक्ष राजमणि को एसपी भारत सोनी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। शुरूआती जांच में यह भी सामने आया है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चौकीदार के भरोसे छोड़ दी गई थी, जिसके कारण भीड़ अनियंत्रित हो गई और समय पर वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी गई।

भगदड़ कांड की जांच के लिए खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज

डीएम ने बताया कि घायल लोगों का इलाज निजी और सरकारी अस्पतालों में चल रहा है और प्रशासन की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। घटना के कारणों को लेकर डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि मंदिर परिसर में भगदड़ कैसे मची, इसकी जांच सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यूपी में औद्योगिक रफ्तार तेज: 9 साल में 17,841 नए कारखाने पंजीकृत

70 साल में 14,178 कारखाने, अब कुल संख्या 32,019

डीएचएस ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर पिछले नौ वर्षों में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है। अप्रैल 2017 से अब तक प्रदेश में 17,841 नए कारखाने पंजीकृत हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या बढ़कर 32,019 हो गई है। तुलना करें तो स्वतंत्रता के बाद 1947 से मार्च 2017 तक लगभग 70 वर्षों में प्रदेश में केवल 14,178 कारखाने ही पंजीकृत हुए थे।

निवेश अनुकूल माहौल से बढ़ा उद्योगों का विस्तार

श्रम एवं रोजगार विभाग के अनुसार, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन स्वीकृति, भूमि बैंक, बेहतर कानून-व्यवस्था और मजबूत आधारभूत ढांचे जैसे कदमों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। सितंबर 2023 से अब तक 10,194 कारखानों का पंजीकरण हुआ है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में ही 4,746 नए कारखाने जुड़े हैं।

16.53 लाख लोगों को मिला रोजगार

अप्रैल 2017 के बाद पंजीकृत कारखानों में वर्तमान में 16,53,179 लोग कार्यरत हैं। इनमें 15,29,907 पुरुष और 1,23,272 महिलाएं शामिल हैं। उद्योगों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को सामाजिक-आर्थिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

पश्चिमी यूपी आगे, सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास

क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 10,895 कारखाने पंजीकृत हुए हैं। इसके अलावा मध्य उत्तर प्रदेश में 3,526, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3,205 और बुंदेलखंड क्षेत्र में 215 कारखाने स्थापित हुए हैं। इससे संकेत मिलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार हुआ है।

सूक्ष्म से बड़े उद्योगों तक संतुलन

प्रदेश में 14,412 कारखाने ऐसे हैं, जहां 100 तक श्रमिक कार्यरत हैं, जबकि 3,213 कारखानों में 101 से 1000 श्रमिक काम कर रहे हैं। इसके अलावा 118 बड़े कारखाने ऐसे हैं, जिनमें 1000 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के साथ बड़े उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की बात सामने आती है।

बिहार में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण पर प्रहार, 1 अप्रैल से चलेगा विशेष अभियान

डीएचएस ब्यूरो

पटना। राज्य सरकार ने राज्यभर में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक और संगठित कार्रवाई का फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों, अपर समाहर्त्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं, अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए 1 अप्रैल 2026 से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में शहरी सौंदर्यीकरण और सुव्यवस्थित विकास के लिए अतिक्रमण हटाना अत्यंत आवश्यक है। सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कर ही हम बेहतर यातायात, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित कर सकते हैं। हालांकि, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। गरीब एवं असहाय लोगों के जीवनयापन को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उनका अतिक्रमण तभी हटाया जाए, जब उनके लिए रोजगार के वैकल्पिक साधन या पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए। वहीं प्रधान सचिव ने निर्देश देते हुए कहा है कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) के तहत विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य है।

सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण पर विशेष चिंता

राज्य सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से सटे सात जिलों के नो मैन्स लैंड में अतिक्रमण के मामलों को अत्यंत गंभीर बताया है। इन मामलों के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सीमांकन के लिए संयुक्त सर्वेक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया है।

पुनर्वास के बिना नहीं हटेगा गरीबों का अतिक्रमण

राज्य सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि गरीब और असहाय लोग अक्सर जीविकोपार्जन के लिए सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करते हैं। इसलिए वेंडिंग जोन या वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अतिक्रमण हटाने से उनके रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें।

जिलाधिकारियों की भूमिका पर स्पष्टता

पत्र में यह भी कहा गया है कि हालांकि जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाना विधिसम्मत है, लेकिन यह न्यायोचित नहीं माना गया है क्योंकि वे इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी होते हैं। ऐसे में अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के अधिकारियों को ही इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं।

शहरी सौंदर्यीकरण से जुड़ा अभियान

अतिक्रमण हटाने को शहरी सौंदर्यीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए सरकार ने इसके लिए वित्तीय आवंटन भी जारी किया है। हाल ही में जारी पत्रों के माध्यम से विभिन्न जिलों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

अभिलेख संधारण और मॉनिटरिंग पर जोर

सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे अतिक्रमण वादों की सूची तैयार करें और उनका विधिवत संधारण करें। प्रत्येक मामले में नोटिस, तामिला और कार्रवाई की वर्तमान स्थिति का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य होगा।

नालंदा में वैश्विक शिक्षा का संगम, 30+ देशों के छात्रों के बीच राष्ट्रपति मुर्मू

राजगीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नालंदा विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर में 2000 सीटों वाले अत्याधुनिक सभागार 'विश्वामित्रालय' का उद्घाटन किया और मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विश्वस्तरीय ज्ञान केंद्र बनने की ओर नालंदा... अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने इस अवसर को भारतीय सभ्यता के शाश्वत ज्ञान परंपरा की पुनर्पुष्टि बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और शिक्षा का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है।

मरणोपरांत नाटक का मंचन

रंगसाथी की ओर से प्रस्तुति, रिश्तों के द्वंद्व पर आधारित कथा

पटना। रंगसाथी नाट्य समूह द्वारा बहुचर्चित नाटक 'मरणोपरांत' का मंचन 31 मार्च 2026 को किया गया। प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित इस नाटक का निर्देशन राहुल कुमार ओझा कर रहे थे।

नाटक की कहानी... 'मरणोपरांत' एक ऐसी कथा है जो एक युवती की मृत्यु के बाद खुलने वाले रहस्यों, संबंधों की जटिलताओं और मनोवैज्ञानिक संघर्षों को केंद्र में रखती है। दुर्घटना में हुई महिला की मौत के बाद उसका पति और प्रेमी आमने-सामने आते हैं, और यहीं से शुरू होता है भावनाओं का गहरा टकराव। कहानी धीरे-धीरे सामने लाती है प्रेम, विश्वास और बेवफाई के छिपे पहलू रिश्तों की ईमानदारी और सच्चाई से जुड़ी बेचैनियों को.

यह नाटक मानसिक उथल-पुथल और दो पुरुषों के बीच का मौन संघर्ष को दशार्ता है

नाटक में प्रेम, अपराधबोध और मानवीय संवेदनाओं की परतों को बेहद संवेदनशील तरीके से कलाकारों ने दिखाया

कलाकार और टीम

मंच पर
राहुल कुमार ओझा -प्रेमी
रत्नेश पांडेय - पति

मंच से परे
प्रस्तुति नियंत्रकः दिग्विजय कुमार तिवारी
संगीतः रामन्यार टारजन, पंकज कौशिक
कॉस्ट्यूमः मीना ओझा, सुभद्रा कुमारी

बसपा से जनता की कई उम्मीदें, संगठन मजबूत कर चुनावी तैयारी करें तेज : मायावती

लखनऊ, (आईएएनएस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) मुखिया मायावती ने मंगलवार को यूपी स्टेट व जिला कमेटी की अहम बैठक की। जिसमे उन्होंने संगठन की जमीनी और आर्थिक मजबूती के साथ चुनावी तैयारियों को तेज करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारों की नीतियों से निराश जनता बसपा से उम्मीद लगाए बैठी है, ऐसे में पार्टी कार्यकताओं को पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करना होगा, किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमेटी की बैठक में पार्टी संगठन के कामकाज की समीक्षा करते हुए मायावती ने निर्देश दिया कि पिछले दिशा-निर्देशों पर अमल की प्रगति रिपोर्ट को और बेहतर किया जाए और सर्वसमाज में पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाई जाए।

मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों पर उदासीनता के कारण आम जनता का जीवन संकट में है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे

बड़े और गरीब राज्य में रोजी-रोटी की समस्या और विकराल हो गई है, वहीं सरकारें अब भी वादों और जुमलेबाजी के सहारे हालात सुधारने का दावा कर रही हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक तनाव के चलते रसोई गैस, पेट्रोल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे गरीब और मेहनतकश वर्ग की

रोहतास की तेलकप पंचायत ने देश में लहराया परचम, मिला दूसरा स्थान

डीएचएस ब्यूरो

पटना। बिहार के रोहतास जिले की तेलकप ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2025 के लिए 'नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार' के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में इस पंचायत को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत की मुखिया अनीता टोप्पो को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिला जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में बिहार की ग्राम पंचायतें तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रही हैं।

राष्ट्रीय पहचान से बढ़ा गौरव

मंत्री ने कहा कि रोहतास प्रखंड की तेलकप ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने इसे अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणादायक बताया।

पंचायतों को सशक्त बनाने पर जोर

उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मियों के लिए राज्य और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय समस्याओं के समाधान और बेहतर नीति निर्माण में मदद मिल रही है।

हर वर्ष दिया जाता है राष्ट्रीय सम्मान

'नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार' केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को प्रदान किया जाता है।

इस पुरस्कार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन को बढ़ावा देना है। तेलकप ग्राम पंचायत की यह उपलब्धि बिहार की अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जा रही है।

बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन पर जल्द फर्राटा भरेंगे वाहन

डीएचएस ब्यूरो

पटना। से जुड़े बख्तियारपुर- बाढ़-मोकामा लिंक पथ के चौड़ीकरण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर यातायात सुगम होगा और लोगों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार, लगभग 45.70 किलोमीटर लंबी इस सड़क को फोरलेन में विकसित किया जा रहा है। 249.881 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस परियोजना को जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे बख्तियारपुर से मोकामा तक की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

कनेक्टिविटी होगी मजबूत

यह लिंक पथ अथमलगोला (बख्तियारपुर-ताजपुर पुल क्षेत्र) से शुरू होकर बाढ़, पंडारक मोड़, शिवनार और मोकामा होते हुए मोकामा बाजार के बाटा चौक तक जाता है। चौड़ीकरण के बाद इस मार्ग से आसपास के क्षेत्रों का जुड़ाव राष्ट्रीय राजमार्ग-31 NH-31) से और बेहतर हो जाएगा।

रोजगार और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

अधिकारियों के अनुसार, सड़क के चौड़ीकरण से कृषि आधारित गतिविधियों और स्थानीय व्यापार को भी गति मिलेगी। बेहतर परिवहन सुविधा से किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। परियोजना के पूरा होते ही बख्तियारपुर-मोकामा के बीच यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

जाम से मिलेगी राहत

पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इस सड़क के तैयार होने से एनएच-31 पर लगने वाले जाम से स्थायी राहत मिलेगी। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से भारी वाहनों और स्थानीय यातायात का दबाव कम होगा।

यूपी के 28 लाख छात्रों को मिली 3350 करोड़ की छात्रवृत्ति, योगी ने दी बड़ी सौगात

डीएचएस ब्यूरो

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में छात्रों और गरीब परिवारों के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता का वितरण किया। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 9-10 तथा दशमोत्तर के 27,99,982 विद्यार्थियों के खातों में 3350 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति सीधे ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 33,334 आश्रित परिवारों को 100 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी जारी की गई।

तकनीक से पारदर्शिता का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तकनीक के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। उन्होंने दावा किया कि पहले व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी के कारण लाभार्थियों को पूरी राशि नहीं मिल पाती थी।

विपक्ष पर निशाना

मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले योजनाओं में भ्रष्टाचार होता था और गरीबों के हक में कटौती की जाती थी। उन्होंने कहा कि अब ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को जेल भेजा जाएगा।

छात्रों को परिश्रम का संदेश

मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह राशि केवल सहारा है, अंतिम लक्ष्य नहीं। उन्होंने छात्रों से मेहनत को प्राथमिकता देने और छात्रवृत्ति का सही उपयोग करने की अपील की।

बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा सभी वर्गों के छात्रों को बिना भेदभाव के शिक्षा से जोड़ने की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 67 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 4800 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है।

गरीब परिवारों को राहत

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता सीधे खातों में दी जा रही है, जिससे उन्हें कठिन समय में सहारा मिल सके।

रोजगार और योजनाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं। हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।

सामाजिक योजनाओं पर जोर

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना और मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार का लक्ष्य सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे।

भाजपा ने खोला आप का पिंक कार्ड वाला भ्रम जाल

आप का दावा पिंक कार्ड एक बार प्रयोग किए जाने के बाद एक घंटे तक दुबारा प्रयोग नहीं हो सकता

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के पिंक कार्ड एक बार प्रयोग किए जाने के बाद एक घंटे तक दुबारा प्रयोग नहीं हो सकता के दावे पर पटलवार करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा यह पूरी तरह दुष्प्रचार है। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने सोमवार को बस बदल बदल कर जा कर देखा और मात्र आधे घंटे में सफलतापूर्वक 3 बार पिंक कार्ड टैब किया। उन्होंने कहा लाखों महिलाओं का पिंक कार्ड बनाने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए बसों में अगले कुछ माह तक पिंक टिकट भी उपलब्ध रहेंगे और डी.टी.सी. को जनप्रतिनिधि कार्यालयों से भी जनता के बीच जा कर पिंक कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और महामंत्री व सांसद कमलजीत सहरावत ने डी.टी.सी. बसों में लागू महिला पिंक कार्ड को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ मीडिया कर्मियों को हथियार बना कर फैलाये जा रहे भ्रम जाल की कड़ी निंदा की है। दोनों ने महिलाओं से इस भ्रम जाल से सावधान रहते हुए अपने पिंक कार्ड को अपनी सुविधानुसार खूब प्रयोग करने का आव्हान किया है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि विगत कुछ दिनों से कुछ मीडिया कर्मियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी नेता महिलाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि पिंक कार्ड को एक बस में टैब कर लिया तो अगले एक घंटे तक यह दुबारा टैब नहीं होगा।

सचदेवा ने कहा है कि यह पूरी तरह दुष्प्रचार है कि पिंक कार्ड एक बार प्रयोग किए जाने के बाद एक घंटे तक दुबारा प्रयोग नहीं हो सकता, कल हमारी महिला मोर्चा की कार्यकताओं ने बस बदल बदल कर जा कर देखा और मात्र आधे घंटे में सफलतापूर्वक तीन बार पिंक कार्ड टैब किया। उन्होंने महिलाओं से अनुरोध किया कि वह दिल्ली में कहीं भी डी.टी.सी. की ई-बसों के साथ ही देवी बसों में पिंक कार्ड अथवा पिंक टिकट लेकर यात्रा करें।

एमसीडी स्थायी समिति में 9 पार्षद लॉटरी से रिटायर

ड्रा के जरिए प्रक्रिया पूरी; आप-भाजपा के पार्षदों के नाम निकले

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। राजधानी में नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति से मंगलवार को कुल 18 में से 9 पार्षदों को ड्रा (लॉट) के माध्यम से पद निवृत्त किया गया। यह प्रक्रिया स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संपन्न हुई।

ड्रा से तय हुआ कार्यकाल समाप्त

बैठक में 12 वार्ड समितियों से चुने गए सदस्यों में से एक-एक सदस्य को पद निवृत्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। डीएमसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पर्चियों के माध्यम से ड्रा निकाला गया, जिसमें 9 पार्षदों का कार्यकाल समाप्त घोषित किया गया।

इन पार्षदों के नाम आए सामने

ड्रा में आम आदमी पार्टी के अंकुश नारंग तथा भारतीय जनता पार्टी के शिखा भारद्वाज, इंद्रजीत सहरावत, नीमा भगत, राजपाल सिंह और अंजू देवी के नाम शामिल रहे।

इसके अलावा, सदन से चुने गए सदस्यों में से आम आदमी पार्टी के मोहिनी जीनवाल और आमिल मलिक तथा भाजपा के पंकज लूथरा भी पद निवृत्त हुए।

वार्ड समितियों से पद निवृत्त सदस्य

शिखा भारद्वाज (भाजपा)
अंजू देवी (भाजपा)
इंद्रजीत सहरावत (भाजपा)
राजपाल सिंह (भाजपा)
नीमा भगत (भाजपा)
अंकुश नारंग (आप)

सदन से चुने गए पद निवृत्त सदस्य

मोहिनी जीनवाल (आप)
आमिल मलिक (आप)
पंकज लूथरा (भाजपा)

इस अवसर पर स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सभी पद निवृत्त सदस्यों के योगदान की सराहना की।

कांग्रेस ने की शीला दीक्षित की प्रतिमा लगाने की मांग, विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

देवेन्द्र यादव बोले, "दिल्ली के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाए"

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की प्रतिमा विधानसभा परिसर में स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के योगदान को देखते हुए उनकी पुण्यतिथि पर यह पहल की जानी चाहिए।

यादव ने अपने पत्र में कहा कि शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के विकास में अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनकी पुण्यतिथि पर विधानसभा में याद किया जाता रहा है, इसलिए शीला दीक्षित की प्रतिमा स्थापित कर हर वर्ष उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित ने राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, प्रदूषण नियंत्रण और दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने में अहम भूमिका निभाई। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उनके कार्य उल्लेखनीय रहे, जिनमें नगर निगम में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, लाडली योजना, महिला आयोग की स्थापना और सुरक्षा से जुड़े कई कदम शामिल हैं।

इससे पहले दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में शीला दीक्षित की 88वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके योगदान को सराहा।

एलजी से मिले देवेंद्र यादव, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दे उठाए

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण के प्रतीक के रूप में पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। मुलाकात के दौरान राजधानी की प्रमुख समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

दिल्ली की ज्वलंत समस्याओं पर की चर्चा

देवेंद्र यादव ने कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली की पूरी आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने राजधानी में बेरोजगारी, महंगाई, खराब कानून-व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, नशे के कारोबार और गोलीबारी जैसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की।

ग्रामीण जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने की मांग

मुलाकात के दौरान दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी उठाया गया। देवेंद्र यादव ने कहा कि वर्तमान सर्किल रेट 55 लाख रुपये है, जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि किसानों के लिए जमीन ही आजीविका का मुख्य साधन होती है और अधिग्रहण के बाद उनका रोजगार प्रभावित होता है।

जल संकट, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं पर चिंता

उन्होंने दिल्ली में बढ़ते जल संकट, वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई, नालों की गाद निकासी, जलभराव, खराब सड़कों और डीटीसी बसों की कमी जैसे मुद्दों को भी उठाया। उनका कहना था कि इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस और समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है।

झुग्गी-झोपड़ी हटाने की कार्रवाई पर सवाल

देवेंद्र यादव ने झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाने की कार्रवाई पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों के सामने आजीविका और आवास का संकट खड़ा हो रहा है। साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों और जे.जे. क्लस्टरों में रहने वाली बड़ी आबादी की खराब जीवन स्थितियों, कूड़ा प्रबंधन और सीवर व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई।

उपराज्यपाल ने दिए आश्वासन

मुलाकात के दौरान उपराज्यपाल ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं पर काम करने का आश्वासन दिया।

सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति का निधन, भारत के लिए क्षति: विजय जौली

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद ह्यचानह्न संतोखी का निधन हो गया है। भाजपा नेता डॉ. विजय जौली ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए इसे भारत के लिए एक बड़ी क्षति बताया है।

भारत-सूरीनाम संबंधों के मजबूत स्तंभ थे संतोखी

जौली ने कहा कि संतोखी भारत और सूरीनाम के बीच सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते रहे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में संतोखी ने संस्कृत भाषा में राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर दोनों देशों के गहरे रिश्तों को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी थी।

कई महत्वपूर्ण पदों पर किया कार्य

संतोखी ने अपने राजनीतिक जीवन में सूरीनाम के न्याय एवं पुलिस मंत्री तथा पुलिस कमिश्नर के रूप में भी कार्य किया। जौली के अनुसार, उन्होंने देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए निरंतर प्रयास किए।

कांग्रेस की घोषणाएं डस्टबिन में, बीजेपी निभा रही हर वादा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

डीएचएस ब्यूरो,

नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसके शासनकाल में घोषणाएं 'डस्टबिन' में चली जाती थीं, जबकि 2014 के बाद भाजपा सरकार हर वादे को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। वह मंगलवार को भिवानी के तोशाम में आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने अपने संकल्प पत्र के वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के 217 वादों में से 60 को डेढ़ साल में पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष पर तेजी से काम जारी है। सैनी ने कहा कि यह सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें लागू भी करती है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि तोशाम हलके में पिछले साढ़े 11 वर्षों में 283 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 258 पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की मजबूत व्यवस्था बनी। ऊर्जा आपूर्ति को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए सैनी ने कहा कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और विपक्ष के भ्रामक प्रचार से सावधान रहें।

मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और अब तक 12 लाख किसानों के खातों में 1.64 लाख करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी आरंभ होगी।

अहिंसा कायरता नहीं, साहस की पराकाष्ठा: विजेंद्र गुप्ता

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। महावीर जयंती के अवसर पर रोहिणी में दिगंबर जैन महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात करने का आह्वान करते हुए कहा कि सच्ची विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण पाने में है।

आत्मनिरीक्षण का पर्व है महावीर जयंती

सभा को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि महावीर जयंती केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और अंतरात्मा को परखने का अवसर है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सभी जीवों के प्रति करुणा रखता है, वही भगवान महावीर के मार्ग पर चलता है।

अहिंसा को बताया सर्वोच्च शक्ति

उन्होंने 'अहिंसा परमो धर्म' के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अहिंसा कायरता नहीं, बल्कि साहस की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने यह सिद्ध किया कि सच्ची वीरता अपने मन, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय पाने में है।

अनेकांतवाद और अपरिग्रह पर दिया बल

गुप्ता ने 'अनेकांतवाद' के सिद्धांत को आज के समाज के लिए बेहद प्रासंगिक बताते हुए कहा कि हर विचार में सत्य का अंश होता है और इसे स्वीकार करना जरूरी है। उन्होंने 'अपरिग्रह' के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमित उपभोग और प्रकृति के प्रति संतुलित दृष्टिकोण आज के वैश्विक संकटों का समाधान दे सकता है।

सिद्धांतों को जीवन में उतारने का आह्वान

उन्होंने लोगों से अपील की कि महावीर जयंती का महत्व तभी सार्थक होगा, जब उनके सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा जाए। उन्होंने कहा कि घरों में अहिंसा, व्यापार में सत्य और जीवन में सादगी अपनाना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान गुप्ता ने जैन संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया और सामुदायिक कार्यों में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। समापन अवसर पर उन्होंने राजधानी में करुणा और सद्भाव की भावना को मजबूत करने का संकल्प भी दोहराया।

फीस बढ़ोतरी और मनमानी पर भड़का नेशनल अकाली दल, आंदोलन की चेतावनी

डीएचएसी ब्यूरो

नई दिल्ली। प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार फीस बढ़ाने और अभिभावकों पर दबाव बनाने के मुद्दे पर नेशनल अकाली दल ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षा संस्थान अपनी मनमानी बंद करें, नहीं तो पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन शुरू करेगी।

पम्मा ने कहा कि बच्चों और उनके अभिभावकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। शिक्षा के नाम पर आर्थिक बोझ डालना गलत है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विक्रांत मोहन और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह मारवाह ने भी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो नेशनल अकाली दल सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।

त्रिवेणी कला संगम में 'शक्ति' का उत्सव, महिला कलाकारों का शानदार प्रदर्शन

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। एनडीएमसी यानी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा त्रिवेणी कला संगम के सहयोग से आयोजित पांच दिवसीय महिला कला कार्यशाला 'शक्ति' का समापन मंगलवार को भव्य कला प्रदर्शनी के साथ हुआ। इस प्रदर्शनी में कार्यशाला के दौरान तैयार की गई विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया, जिसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।

महिला सृजनात्मकता का अनूठा उत्सव

27 से 31 मार्च तक आयोजित इस कार्यशाला में देशभर की 20 प्रमुख महिला कलाकारों ने भाग लिया। कलाकारों ने विभिन्न माध्यमों के जरिए 'शक्ति' विषय को प्रस्तुत करते हुए महिला की ताकत, साहस और सृजनात्मकता को रेखांकित किया।

कलाकारों को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम के अंतिम दिन एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और भाग लेने वाली महिला कलाकारों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कलाकार रामेश्वर ब्रूटा, अमिताभ दास और अमर जी सहित कई कला प्रेमी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

'शक्ति' कला कार्यशाला का भव्य समापन

कला के माध्यम से सामाजिक बदलाव पर जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चहल ने कहा कि कला हमेशा से पहचान, अभिव्यक्ति और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम रही है। 'शक्ति' कार्यशाला का उद्देश्य समकालीन कला के जरिए भारत में महिलाओं की बदलती भूमिका अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझना और प्रस्तुत करना है। उन्होंने बताया कि इस पहल ने महिला कलाकारों को समानता, पहचान और आत्म-अभिव्यक्ति जैसे विषयों पर विचार रखने का मंच दिया, जहां पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण का समन्वय देखने को मिला।

वार्षिक आयोजन बनेगी 'शक्ति' कार्यशाला

चहल ने घोषणा की कि 'शक्ति' कार्यशाला को अब एनडीएमसी के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही नेहरू पार्क में मूर्तिकला पार्क विकसित किए जाने की योजना भी जल्द साकार होगी। उन्होंने यह भी बताया कि एनडीएमसी कला और संस्कृति के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

कला और महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

इस अवसर पर कहा गया कि यह पहल कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह मंच महिला कलाकारों को अपनी प्रतिभा और विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। कार्यशाला में वसुंधरा तिवारी ब्रूटा, कंचन चंदर, सीमा कोहली, बुला भट्टाचार्य, संगीता मूर्ति, तारा शर्मा, इंदु त्रिपाठी, विजया वेद, सूर्यस्नाता मोहंती, अनीता तंवर, रीना सिंह, कंचन प्रकाश, श्वेता राय, शम्पा भट्टाचार्जी, संगीता सिंह, सुरभि शुभम, मोइत्रेयी कुमार, मीनाक्षी झा, अंजुम खान और सुमिता कथूरिया सहित कई कलाकारों ने भाग लिया। समापन समारोह में कला प्रेमियों, विद्यार्थियों, एनडीएमसी के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

page-04_page05.qxd 31-03-2026 21:46 Page 1

स्पेस में ऐसे पौधे उगाते एस्ट्रोनॉट्स, जानिए 'वेजी' सिस्टम

इंसान जैसे-जैसे गहरे अंतरिक्ष की यात्रा की तैयारी कर रहा है, पौधों का महत्व और बढ़ गया है। सिर्फ सुंदरता या ऑक्सीजन के लिए नहीं बल्कि ताजे भोजन, विटामिन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अंतरिक्ष में पौधे उगाना जरूरी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इसी उद्देश्य के साथ स्पेस स्टेशन पर 'वेजी' नामक एक खास वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम के साथ काम करता है, जिसका नाम वेजी है। वेजी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगा एक छोटा सा 'स्पेस गार्डन' है। यह एक कैरी-ऑन बैग के आकार का सिस्टम है, जिसमें आमतौर पर छह पौधे एक साथ

उगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य माइक्रोग्रैविटी में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना और अंतरिक्ष यात्रियों को ताजा, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

वेजी में प्रत्येक पौधा मिट्टी आधारित तकिए में उगाया जाता है। इन तकियों में विशेष उर्वरक और विकास के लिए तत्व भरा होता है। ये तकिए जड़ों तक पानी, पोषक तत्व और हवा का सही संतुलन बनाए रखते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण पानी बुलबुले बना लेता है, इसलिए यह संतुलन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। पौधों को ऊपर एलईडी लाइट्स रोशनी देता है। चूंकि पौधे लाल और नीली रोशनी का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए वेजी का चैंबर अक्सर गुलाबी-लाल रंग में चमकता दिखाई देता है। वेजी में अब तक कई प्रकार के पौधे सफलतापूर्वक उगाए जा चुके हैं, जिनमें लेट्यूस की तीन किस्में, चाइनीज कैबेज, मिजुना सरसों, लाल रशियन केल और खूबसूरत जिनिया के फूल शामिल हैं। कुछ पौधों को क्रू सदस्यों ने तोड़कर खाया भी, जबकि बाकी नमूनों को पृथ्वी पर अध्ययन के लिए भेजा गया। अंतरिक्ष में लंबे मिशनों पर ताजे फल-सब्जियां सिर्फ पोषण ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी हैं।

नासा का मानना है कि पौधे उगाना उन्हें पृथ्वी से जोड़कर रखता है और तनाव कम करता है। वेजी के अलावा नासा ने 'एडवांस प्लांट हैबिटल' (एपीएच) भी विकसित किया है। एपीएच वेजी से ज्यादा उन्नत और पूरी तरह स्वचालित सिस्टम है। इसमें 180 से ज्यादा सेंसर लगे हैं, जो पृथ्वी पर बैठी टीम को लगातार जानकारी देते रहते हैं। एपीएच में बौनी गेहूं जैसे पौधों का परीक्षण किया जा चुका है। भविष्य में नासा टमाटर, मिर्च, बेरी और अन्य पौधे उगाने की योजना बना रहा है। ये न सिर्फ पोषण देंगे बल्कि रेडिएशन से भी कुछ सुरक्षा प्रदान करेंगे। (आईएएनएस)

संपादकीय

जनगणना में जातिः सामाजिक न्याय या विभाजन की शुरूआत?

स्वतंत्रता के बाद भारत की आठवीं जनगणना अब अंततः शुरू होने जा रही है। 2021 में होनी वाली यह जनगणना कोविड महामारी और अन्य कारणों से विलंबित रही, लेकिन अब यह डिजिटल रूप में दो चरणों में पूरी की जाएगी। गोपनीयता के नए नियमों के साथ यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल एप, वेब पोर्टल और वास्तविक समय की निगरानी का उपयोग किया जाएगा। पारंपरिक कागज-पत्रों की जगह डिजिटल माध्यम से जानकारी एकत्र करने से समय और संसाधनों की बचत होगी, त्रुटियाँ कम होंगी और ब्योरा सीधे सर्वर पर पहुँचकर प्रक्रिया को तेज तथा सटीक बनाएगा।इस जनगणना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। जनगणना आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि एकत्रित सभी विवरण पूर्णतः गोपनीय रखे जाएँगे। लोगों को अपनी जानकारी ह्यनीर-क्षीरह्न ढंग से दर्ज करनी होगी, ताकि कोई भी गोपनीयता भंग न हो। डिजिटल जनगणना न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य की नीति-निर्माण में भी अधिक विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध कराएगी।लेकिन इस जनगणना का सबसे चर्चित पहलू स्वतंत्र भारत में पहली बार जातियों का विवरण एकत्र करना है। 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई थी। इसलिए, लगभग सौ वर्ष पुराने आँकड़ों पर आधारित विभिन्न जातीय समूहों के दावे अब सत्यापित हो सकेंगे। कुछ समूह अपनी संख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को लेकर ऊँचे दावे करते रहे हैं, जबकि वास्तविकता बदल चुकी है। डिजिटल जनगणना के माध्यम से देश की सामाजिक-आर्थिक और जातीय स्थिति की अपेक्षाकृत अधिक परिपूर्ण तस्वीर सामने आएगी। इससे विभिन्न योजनाओं, आरक्षण नीतियों और विकास कार्यक्रमों को अधिक लक्षित और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।जातीय गणना के सकारात्मक पक्ष को नकारा नहीं जा सकता। यह धारणाओं को ध्वस्त करेगी और वास्तविक आँकड़ों के आधार पर सामाजिक न्याय की दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करेगी। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य समूहों की सही स्थिति जानने से सरकार बेहतर नीतियाँ बना सकेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी क्षेत्रों में संसाधनों का उचित वितरण संभव होगा।फिर भी, इस प्रक्रिया से जुड़ी कुछ गंभीर आशंकाएँ हैं। जातिगत जनगणना के आँकड़े सामने आने के बाद कहीं जातिवाद की राजनीति बेलगाम न हो जाए, यह चिंता जायज है। कई राजनीतिक दल पहले से ही जाति को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। नए आँकड़ों के आधार पर आरक्षण की माँगें बढ़ सकती हैं, नए समूह आरक्षण की लिस्ट में शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं और इससे सामाजिक विभाजन गहरा हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जातिवादी राजनीति अक्सर वैमनस्य, टकराव और समाज में दरार पैदा करती है। यदि जनगणना के आँकड़ों का दुरुपयोग संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए किया गया, तो इसका नुकसान पूरे राष्ट्र को होगा।इसलिए, सरकार को सतर्क रहना चाहिए। जातिगत जनगणना का उद्देश्य किसी की स्वार्थी राजनीति या वोट बैंक बनाने नहीं, बल्कि शासन की नीतियों को अधिक प्रभावशाली और न्यायपूर्ण बनाने का होना चाहिए। सरकार को ऐसे कानूनी और प्रशासनिक उपाय करने चाहिए कि ये आँकड़े केवल नीति-निर्माण और विकास कार्यों के लिए उपयोग हों, न कि आरक्षण की नई-नई माँगों या जातिवादी ध्रुवीकरण के लिए। जाति के आधार पर राजनीति को सीमित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि जनगणना राष्ट्र-निर्माण का माध्यम बने, न कि विभाजन का।डिजिटल जनगणना एक ऐतिहासिक अवसर है। यह न केवल तकनीकी रूप से आधुनिक है, बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं को समझने का भी माध्यम है। यदि इसे सही दिशा में उपयोग किया गया, तो भारत अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और विकसित राष्ट्र बन सकता है। लेकिन यदि जातिगत आँकड़ों को राजनीतिक हथियार बना दिया गया, तो यह अवसर गंवाया जा सकता है। सरकार, राजनीतिक दल और नागरिकों को सामूहिक जिम्मेदारी समझनी होगी। जनगणना के आँकड़ों का सम्मानजनक और राष्ट्रीय हित में उपयोग ही सच्ची प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। डिजिटल युग की यह पहली जनगणना सफल हो और देश को सही दिशा दे यही अपेक्षा है।

साहित्य अकादमी का एलजीबीटीक्यू लेखक सम्मेलन, हमारी संस्कृति पर आक्रमण

भारत की सर्वोच्च साहित्यिक संस्थाओं में से एक, साहित्य अकादमी द्वारा (एलजीबीटीक्यू) लेखक सम्मेलन का आयोजन एक गहरे वैचारिक विमर्श और टकराव का संकेत है। दुखद है कि यह सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, के तत्वावधान में हो रहा है। संस्कृति मंत्रालय को यह देखना चाहिए कि क्या हमारी संस्कृति के सभी सिरमौर विषयों पर क्या साहित्य अकादमी ने चर्चा सम्पन्न करा ली है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को इस साहित्य आकादमी से पूछना होगा, कि 'भारतीय ज्ञान परंपरा की कितनी चर्चा और कितने लेखक सम्मेलन 'साहित्य अकादमी' ने करा लिए हैं? क्या हमारे सभी ज्वलंत और आवश्यक सांस्कृतिक प्रश्न उत्तर पा चूकें है जो इस प्रकार के विषय को चर्चा केंद्र में रखने का निर्णय लिया गया? प्रश्न यह नहीं है कि किसी विषय पर चर्चा क्यों हो रही है, बल्कि यह है कि किन विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है और उसके पीछे कौन-सी वैचारिक शक्तियाँ सक्रिय हैं?

हम एलजीबीटीक्यू के मौलिक अधिकारों के विरोध में नहीं हैं किंतु इनके कंधों पर रखकर भारतीय मूल्यों, देशज अधिष्ठानों, हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं पर जिस प्रकार बंदूकें चलाई जा रही हैं उसके विरोध में हैं। भारत में एलजीबीटीक्यू के माध्यम से ये वैचारिक नक्सलाइट्स बहुधा ही गंद फैलाते रहते हैं। यह उनके प्रति संवेदना के लिए नहीं अपितु देश में अनावश्यक वितंडा खड़ा करने के लिए किया जाता है।

हमें यह देखना चाहिए कि वे कौन सी छिपी हुई शक्तियाँ हैं जो भारत में बालक, बालिकाओं के लिए एक से बाथरूम चाहती हैं? ये मार्क्सिस्ट शक्तियाँ विद्यालयों के बालक बालिकाओं को एक ही हास्टल में एक ही कक्ष में रखें जाने की वकालत करती हैं। साहित्य अकादमी का यह लेखक सम्मेलन इन सब बातों की ही तो चर्चा करेगा। इसका लक्ष्य केवल भारतीय परंपराओं पर तोप दागना ही तो होगा। गे और लेस्बियन सेक्स के ऊपर लेखक सम्मेलन में किस प्रकार की चर्चा आएगी, इसकी कल्पना से हृदय सिहर उठता है।

लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर की चर्चा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान वाले, साहित्य अकादमी के आयोजन में आना एक खतरनाक वैचारिक विस्फोट है। यह वैचारिक बारूदी सुरंगें हैं जो हमारे वैचारिक अधिष्ठान के नीचे लगातार बिछाई जा रही हैं।

ट्रांसजेंडर या किन्नर समाज के प्रति सदैव ही हमारे भारतीय समाज का, शास्त्रों का, ऋषि परंपरा का संवेदनशील मंतव्य रहा है। ये हमारी परंपराओं में स्थायी रूप से सम्मानपूर्वक बसे हैं। समय के साथ-साथ इनके विषय में आवश्यक निर्णय लिए जाने चाहिए, जो कि शासन से लेकर समाज तक लिए भी गए हैं। किंतु ट्रांसजेंडर के अतिरिक्त ये जो गे, लेस्बियन क्वीर आदि हैं इनका स्थान हमारे समाज में कहाँ होना चाहिए?

आज भारत में एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि यह पूरा विमर्श तथाकथित 'कल्चरल मार्क्सिज्मह्न की रणनीति का हिस्सा है। इस विचारधारा का मूल उद्देश्य हमारे समाज की पारंपरिक संरचनाओं, परिवार, धर्म, संस्कृति और नैतिकता, को धीरे-धीरे दुर्बल करना ही है। हमारी ऋषि परंपरा और सनातनी संस्कृति

डॉ. प्रवीण दाताराम गुगनानी

को हटाकर उनकी जगह एक नए प्रकार की वैचारिक संरचना स्थापित करना ही ऐसे आयोजनों का लक्ष्य होता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को इस देशज वर्ग के विचारों का आदर करते हुए इस विषय को साहित्य अकादमी के आयोजन से अलग करवाना चाहिए।

भारतीय संस्कृति की जड़ें अत्यंत गहरी और संतुलित हैं। यहाँ मनुष्य को केवल उसकी इच्छाओं या प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके धर्म, कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के आधार पर देखा गया है। ऋषि परंपरा ने जीवन को चार पुरुषार्थ - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष - में संतुलित किया है। इस व्यवस्था में 'काम' मयार्दा और संतुलन के भीतर है, न कि उच्छृंखल अभिव्यक्ति के रूप में। 'काम आनंद' की एक परिपूर्ण परिभाषा, परिधि, प्रतीति, अभिव्यक्ति हमारे पास युगों से हैं। हमारी 'विवाह संस्था' को चोटिल करने का दुष्प्रयास है यह लेखक सम्मेलन। हमारी चिति पर यह नई विध्वंसक मान्यताएँ लादकर वैचारिक बलात्कार किया जा रहा है?

एलजीबीटीक्यू जैसे विषयों को जिस प्रकार से आज शो आफ किया जा रहा है, वह भारतीय दृष्टिकोण से अधिक पश्चिमी अवधारणाओं से प्रेरित है। यह केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं है, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी इसका प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव पड़ता है। इस दुष्प्रभाव की चिंता करनी चाहिए।

यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश में राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन हुआ है और राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्थन मिला है। लेकिन क्या वास्तव में व्यवस्था बदली है? हमारी शासन व्यवस्था राष्ट्रीयता की उपेक्षा क्यों करती है? अनजाने में हमारी सत्ता क्यों पश्चिमी मूल्यों की पक्षधर बनकर खड़ी हो जाती है? यह एक गंभीर प्रश्न है।

कई उदाहरण यह संकेत देते हैं कि शैक्षणिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थानों में अब भी वामपंथी विचारधारा का गहरा प्रभाव बना हुआ है। चाहे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम हों, इतिहास लेखन हो या साहित्यिक संस्थाओं के कार्यक्रम, बहुधा वही दृष्टिकोण प्रमुख होता है जो भारत की परंपरागत मान्यताओं से भिन्न है और उसके विरोध में है।

साहित्य अकादमी का यह निर्णय भी इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। प्रश्न स्वाभाविक है कि जब देश में ग्रामीण साहित्य, वेद-उपनिषद, भारतीय भाषाओं के संरक्षण, या राष्ट्रीय साहित्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तब एलजीबीटीक्यू जैसे विषय को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है?

भारत का 'कथित बुद्धिजीवीह्न वर्ग सदैव ही स्वयं को प्रगतिशील और उदारवादी बताता है, लेकिन इसके विचारों में एक स्पष्ट झुकाव वामपंथी सोच की ओर होता है। यह वर्ग भारतीय परंपराओं को पिछड़ा बताने में संकोच नहीं करता, जबकि पश्चिमी विचारों को आधुनिकता का प्रतीक मानता है। यह वही वर्ग है जो रामायण और महाभारत पर प्रश्न उठाता है। यह वर्ग परंपरागत परिवार व्यवस्था को चुनौती देता है। यह वर्ग भारतीय संस्कृति को 'पितृसत्तात्मकह्न या 'रूढ़िवादीह्न कहकर खारिज करने का प्रयास करता है।

एलजीबीटीक्यू लेखक सम्मेलन जैसे आयोजन इनके लिए केवल साहित्यिक मंच नहीं, बल्कि एक वैचारिक विध्वंस और बारूदी सुरंग फैला देने का माध्यम है। कल्चरल मार्क्सिज्म की अवधारणा यह कहती है कि यदि किसी समाज को बदलना है, तो उसकी संस्कृति को बदलें। भारत में यह प्रक्रिया धीरे-धीरे विभिन्न माध्यमों से चल रही है, फिल्मों, वेब सीरीज, शिक्षा और अब साहित्यिक मंचों के माध्यम से।

बड़ा ही सीधा सा उद्देश्य है इनका। हमारे पारंपरिक मूल्यों को 'पुरानाह्न और 'अप्रासंगिकह्न साबित करना, नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से दूर करना, और जड़विहीन पहचान निर्मित करना। अब देखते हैं इस नए मार्क्सिस्ट वितंडे 'एलजीबीटीक्यू लेखक सम्मेलन' का आयोजन होता है या 'भारतीय ज्ञान परंपरा - लेखक सम्मेलन' होता है। यह भी देखते हैं कि, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के कंधों पर चढ़कर हमारी नियति, हमारी संस्कृति को कौन तय करेगा? ऋषि वंशज तय करेंगे या पश्चिम की औलादें और बाजारवादी ताकते तय करेंगी। **लेखक के निजी विचार हैं।**

1 अप्रैल को पूर्णिमा व्रतः सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ अमृतकाल

हिन्दू धर्म में पूर्णिमा व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 1 अप्रैल बुधवार को चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण रूप में प्रकाशित होता है, इसलिए चंद्रोपासना और व्रत रखने से मानसिक शांति, समृद्धि और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दक पंचांग के अनुसार, बुधवार को सूर्योदय 6 बजकर 11 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 39 मिनट पर होगा। वहीं, चंद्रोदय शाम 6 बजकर 11 मिनट पर होगा। तिथि चतुर्दशी सुबह 7 बजकर 6 मिनट तक, इसके बाद पूर्णिमा है। नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी दोपहर 4 बजकर 17 मिनट तक, इसके बाद हस्त रहेगा। योग वृद्धि दोपहर 2 बजकर 51 मिनट तक, करण वणिज सुबह 7 बजकर 6 मिनट तक रहेगा।

शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 39 मिनट से 5 बजकर 25 मिनट तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक, गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 38 मिनट से 7 बजकर 1 मिनट तक और अमृत काल सुबह 8 बजकर 48 मिनट से 10 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। वहीं, सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 4 बजकर 17 मिनट से अगले दिन सुबह 6 बजकर 10 मिनट तक रहेगा और रवि योग सुबह 6 बजकर 11 मिनट से दोपहर 4 बजकर 17 मिनट तक रहेगा।

अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल दोपहर 12 बजकर 25 मिनट से 1 बजकर 59 मिनट तक, यमगंड सुबह 7 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 10 बजकर 52 मिनट से दोपहर 12 बजकर 25 मिनट तक रहेगा। दुमुर्हूर्त दोपहर 12 बजे से 12 बजकर 50 मिनट तक रहेगा। बुधवार को भद्रा भी रहेगा, जो कि सुबह 7 बजकर 6 मिनट से शाम 7 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। 1 अप्रैल को पूर्णिमा व्रत रखने वाले भक्त सुबह से व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन उपवास रख सकते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, सत्यनारायण कथा या लक्ष्मी-विष्णु पूजन विशेष फलदायी होता है। पूर्णिमा के दिन दान-पुण्य करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।

भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता

वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, स्वदेश में उत्पादन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक शीर्षक से सोमवार को हमारे संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख में हमने भारतीय दवा उद्योग की वैश्विक यात्रा पर चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, आज हम भारत-यूके, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे।

जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए), भारत के फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा करता है। इस समझौते के तहत, 56 फार्मास्युटिकल टैरिफ लाइनों की शुल्क मुक्त बाजार तक पहुंच हो सकेगी, जिससे ब्रिटेन में भारतीय जेनेरिक दवाएं अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगी। गौरतलब है कि ब्रिटेन यूरोप में भारत का सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल निर्यात बाजार बना हुआ है। यह समझौता कई चिकित्सा उपकरणों के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच भी प्रदान करता है, जिनमें सर्जिकल उपकरण, नैदानिक उपकरण, ईसीजी मशीनें और एक्स-रे सिस्टम शामिल हैं। इससे भारतीय निमार्ताओं के लिए लागत कम होने और ब्रिटेन के बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धिता मजबूत होने की उम्मीद है।

दिसंबर 2025 में संपन्न भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय औषधि निर्यात के लिए अवसरों का विस्तार हुआ है। इस समझौते में उन लगभग 90 टैरिफ श्रेणियों में फार्मास्यूटिकल उत्पादों को शुल्क मुक्त करने का प्रावधान किया गया है जिनमें पहले 5 प्रतिशत तक प्रशुल्क लगता था। इसलिए इस समझौते से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यापार को मजबूती मिलने की संभावना है जिससे भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पादन परिवेश के विकास में सहायता मिलेगी। फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार-संचालित हस्तक्षेप

सरकार की रणनीति के केंद्र में 'उत्पादन आधारित प्रोत्साहन' (पीएलआई) योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य घरेलू मेन्युफेक्चरिंग को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना और फार्मास्युटिकल, बल्क ड्रग्स तथा चिकित्सा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देना है। बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्कों, उद्योग सहायता पहलों और अनुसंधान प्रोत्साहन उपायों के साथ मिलकर ये योजनाएं मेन्युफेक्चरिंग क्षमता का विस्तार कर रही हैं, बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही हैं और एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फार्मास्युटिकल केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ कर रही हैं।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा लागू की गई उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में घरेलू मेन्युफेक्चरिंग को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयासों की आधारशिला हैं। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप, फार्मास्यूटिकल्स और बल्क ड्रग्स के लिए पीएलआई योजनाओं के तहत, सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई), प्रमुख शुरूआती सामग्री (केएसएम) और ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) के 3,591 करोड़ रुपये मूल्य के आयात को रोकने में सफलता मिली है। इस प्रकार, ये योजनाएं आयात निर्भरता में औसत दर्जे की कमी लाने और भारत के मेन्युफेक्चरिंग क्षमता को सुदृढ़ करने में योगदान दे रही हैं।

यह योजना उच्च-मूल्य वाले बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों, जटिल जेनेरिक्स और ऑटोइम्यून दवाओं के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देती है, जिससे बिक्री, निर्यात और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। सितंबर 2025 तक 17,274.96 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले, इस योजना के तहत 40,890 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। 2021 में अपनी शुरूआत के बाद से सितंबर 2025 तक कुल बिक्री 3,16,797 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। इस कुल बिक्री में से 2,03,730 करोड़ रुपये का योगदान निर्यात का है। सितंबर 2025 तक, इस योजना के तहत लगभग 97,000 लोगों को रोजगार दिया गया है, जिनमें संविदा और प्रशिक्षु कर्मचारी शामिल हैं। बल्क ड्रग्स (एपीआई/केएसएम/ डीआई) के लिए पीएलआई योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना और किसी एक स्रोत या देश पर निर्भरता को कम करना है।

सितंबर 2025 तक 26 महत्वपूर्ण एपीआई/केएसएम के लिए प्रति वर्ष 55,100 मीट्रिक टन की कुल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता स्थापित की गई है। शुरूआत (2022) से अब तक की संचयी बिक्री 2,313.16 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिसमें 508.12 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। योजना के तहत 4,329.95 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,763.34 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 4,929 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किया गया है। चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने हेतु पीएलआई योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और बड़े निवेश को आकर्षित करना है। इस योजना के तहत कुल बिक्री 12,344.37 करोड़ रुपये रही, जिसमें 5,869.36 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। योजना के माध्यम से 1,093.69 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है। स्रोतःपीआईबी

चिकित्सा उपकरण पार्कों को प्रोत्साहन देने की योजना

इस योजना का उद्देश्य एक ही स्थान पर साझा परीक्षण और प्रयोगशाला सुविधाएं/केंद्र प्रदान करना है जिससे उत्पादन व्यय में उल्लेखनीय कमी आएगी और देश में चिकित्सा उपकरण निर्माण के लिए मजबूत परिवेश बनाने में मदद मिलेगी। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश (ग्रेटर नोएडा), मध्य प्रदेश (उज्जैन) और तमिलनाडु (कांचीपुरम) में तीन पार्कों की स्थापना की जा रही है जो विकास के उन्नत चरण में हैं। इन पार्कों का कुल परियोजना व्यय 871.11 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार इनमें से हरेक पार्क में साझा अवसंरचना सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दे रही है। दिसंबर 2025 तक इन पार्कों में 199 चिकित्सा उपकरण निमार्ताओं को कुल 306.64 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी थी। इनमें से 34 इकाइयों ने अपने संयंत्रों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का उद्देश्य देश भर में किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुंच में सुधार लाना है। पीएमबीजेपी के माध्यम से प्रतिबद्ध दुकानों के व्यापक नेटवर्क के जरिए नागरिकों के दवाओं पर होने वाले खर्च को घटाने तथा आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की तर्कसंगत मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

ओशो की कहानी

शिकायत

मैं तुमसे एक कहानी कहता हूं एक बहुत सुंदर कहानी। इसे जितना संभव हो सके उतनी गहराई से सुनो। एक महिला और उसका छोटा सा बच्चा समुंद्र की लहरों पर अठखेलियां करू रहे थे, और पानी का बहाव काफी तेज था। उसने अपने पुत्र की बांह मजबूती से पकड़ रखी थी और वे प्रसन्नतापूर्वक जलक्रीड़ा में संलग्न थे, कि अचानक पानी की एक विशाल भयानक तरंग उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने भयाक्रांत होकर उसको देखा, ज्वार की यह लहर उनके ठीक सामने ही ऊपर और ऊपर उठती चली गई, और उनके ऊपर छा गई। जब पानी वापस लौट गया तो वह छोटा बच्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। शोकाकुल मां ने मेल्विन, मेल्विन तुम कहां हो? मेल्विन! चिल्लाते हुए पानी में हर तरफ उसको खोजा। जब यह स्पष्ट हो गया कि बच्चा खो गया है, उसे पानी सागर में बहा ले गया है, तब पुत्र के वियोग में व्याकुल मां ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाई और प्रार्थना की, ओह, प्रिय और दयालु परम पिता, कृपया मुझ पर रहम कीजिए और मेरे प्यारे से बच्चे को वापस कर दीजिए। आपसे मैं आपके प्रति शाश्वत आभार का वादा करती हूं। मैं वादा करती हूं कि मैं अपने पति को पुनः कभी धोखा नहीं दूंगी; मैं अब अपने आयकर को जमा करने में दुबारा कभी धोखा नहीं करूंगी; मैं अपनी सास के प्रति दयालु रहूंगी; मैं सिगरेट पीना और सारे व्यसन छोड़ दूंगी! सभी गलत शौक, बस केवल कृपा करके मेरा पक्ष लीजिए और मेरे पुत्र को लौटा दीजिए। बस तभी पानी की एक और दीवार प्रकट हुई और उसके सिर पर गिर पड़ी।जब पानी वापस लौट गया तो उसने अपने छोटे से बेटे को वहां पर खड़ा हुआ देखा। उसने उसको अपनी छाती से लगाया, उसको चूमा और अपने से चिपटा लिया। फिर उसने उसे एक क्षण को देखा और एक बार फिर अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठा दीं। ऊपर की ओर देखते हुए उसने कहा, लेकिन उसने हैट लगा रखा था। मन यही है, बच्चा वापस आ गया है, लेकिन हैट खो गया है।

लोकसभा में आज पेश होगा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक

अमरावती,आईएएनएस। आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 पेश करने जा रही है। इस विधेयक के जरिए अमरावती को आधिकारिक तौर पर राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह फैसला तेलुगुदेशम पार्टी (टीडीपी) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की उस नीति को कानूनी रूप देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिस पर वह लंबे समय से काम कर रही थी। इससे पहले 28 मार्च को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसने इस विधेयक के लिए रास्ता साफ किया। दरअसल, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत राज्य के विभाजन के बाद हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी बनाया गया था। इस व्यवस्था की समय सीमा अधिकतम 10 साल तय की गई थी, जिसके बाद हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी बनना था और आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी स्थापित करनी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने विचार-विमर्श, योजना और परामर्श के बाद अमरावती को नई राजधानी के रूप में चिन्हित किया। इस दिशा में प्रशासनिक, विधायी और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े कदम उठाए गए, ताकि अमरावती को एक पूर्ण विकसित राजधानी के रूप में स्थापित किया जा सके। अब प्रस्तावित संशोधन विधेयक के जरिए 2014 के कानून की धारा 5(2) में बदलाव कर अमरावती का नाम आधिकारिक रूप से राज्य की राजधानी के तौर पर शामिल किया जाएगा। यह संशोधन 2 जून 2024 से प्रभावी माना जाएगा। आंध्र सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य की राजधानी को लेकर किसी भी तरह की अस्पष्टता को खत्म करना और कानूनी रूप से स्पष्ट स्थिति देना है। इस कदम को आंध्र प्रदेश के विकास और प्रशासनिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अधिकारियों को चेतावनी

देहरादून, आईएएनएस। देहरादून में हाल ही में हुई कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम धामी के निर्देश पर सोबन सिंह, उप आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 मसूरी, जनपद-देहरादून और प्रभारी कुठालगेट चौकी उपनिरीक्षक ना.पु अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेशभर में तत्काल प्रभाव से व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जाए और सभी अवांछित एवं हुड़दंग करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रोड रेज, फायरिंग और देर रात तक चलने वाली अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जनता की सुरक्षा है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को पूरी सख्ती और मुस्तैदी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने साफ कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून में हालिया घटना के बाद संबंधित अधिकारियों के निलंबन को इसी सख्ती का उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। उधर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में शहर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने रोड रेज और हुड़दंग की घटनाओं के बढ़ने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाए जाने और हुड़दंगियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने देहरादून शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने एसएसपी देहरादून को अपने सभी थानेदारों को पीक ऑवर में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डे-नाईट पेट्रोलिंग के साथ ही मॉर्निंग पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया जाए। मुख्य सचिव ने बार और रेस्टोरेंट क्लोजिंग के लिए निर्धारित समय को कठोरता से लागू करने के निर्देश दिए।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग, मोदी का साणंद को उपहार

» **अहमदाबाद, आईएएनएस।**

गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यहां केन्स सेमीकॉन की आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक बाजार में एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लायर के रूप में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि साल 2021 में भारत ने 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' की शुरूआत की थी। यह मिशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास की घोषणा है। इस मिशन के तहत देश के छह राज्यों में 1.60 लाख करोड़ रुपए के 10 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने हालिया उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 28 फरवरी को माइक्रॉन के प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हुआ था और अब 31 मार्च को केयन्स टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उत्पादन भी शुरू हो गया है। यह महज संयोग नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कितनी तेजी से विकसित हो रहा है।

उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि एक भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में रुचि दिखाई और आज उसके नतीजे सामने हैं। पीएम मोदी ने कहा, 'भारत की अपनी कंपनी केयन्स टेक्नोलॉजी अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा बन चुकी है। यह एक शानदार शुरूआत है और देश के लिए गर्व का पल है।'

> पीएम मोदी ने हालिया उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 28 फरवरी को माइक्रॉन के प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हुआ था और अब 31 मार्च को केयन्स टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उत्पादन भी शुरू हो गया है। यह महज संयोग नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कितनी तेजी से विकसित हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भारत की कई कंपनियां ग्लोबल सहयोग के जरिए दुनिया को एक मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने में अहम भूमिका निभाएंगी। आज का दिन 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के विजन को सही मायनों में साकार करता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 21वीं सदी सिर्फ आर्थिक प्रतिस्पर्धा का समय नहीं है, बल्कि यह भविष्य की टेक्नोलॉजी को दिशा देने का दौर है। भारत अब सिर्फ बदलाव का साक्षी नहीं है, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस दशक में भारत जो टेक्नोलॉजी पहल कर रहा है, वे आने वाले दशकों में देश की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को और मजबूत करेंगी।

कांकेर में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता, दो हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

» **कांकेर, आईएएनएस।**

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतिम चरण में पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। कोयलीबेड़ा इलाके के दो हार्डकोर नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की पहचान शंकर और हिडमा के रूप में हुई है।

इनमें से एक नक्सली ने एके-47 राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया। दोनों लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे और इलाके में कई घटनाओं में शामिल रहे थे। पुलिस के लगातार दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। कांकेर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब भी लगभग 15 नक्सली ऐसे हैं, जो अभी मुख्यधारा में नहीं लौटे हैं। पुलिस का मानना है कि इन नक्सलियों को भी जल्द ही आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और नक्सलियों को समझाने के साथ-साथ उन्हें बेहतर जीवन का विकल्प भी दिया जा रहा है। आत्मसमर्पण की यह कार्रवाई कांकेर पुलिस के समक्ष पूरी प्रक्रिया के तहत की गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस अधिकारियों ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है, जिससे वे सामान्य जीवन जी सकें। कांकेर के

पुलिस अधीक्षक ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नक्सल उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान में यह एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाना भी है। बताया जा रहा है कि इस सफलता से यह साफ हो चुका है कि कांकेर जिले में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और आने वाले समय में इसके और बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

राहुल गांधी ने पूर्व सैन्य अधिकारी की गोली लगने से मौत को लेकर उत्तराखंड सरकार पर साधा निशाना

» **नई दिल्ली, आईएएनएस।**

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजधानी देहरादून में सेना के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर वीके जोशी की गोली लगने से मौत को लेकर उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाए।

उन्होंने रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत पर चिंता जताते हुए कहा कि उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरहद पर देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले ही आज अपने शहर में ही असुरक्षित हैं। आज उत्तराखंड, भाजपा के गैर-जिम्मेदार नेतृत्व में हिंसा, हत्या और भय के साये में सिमट कर रह गया है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, '' देहरादून में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर वीके जोशी जी की दिनदहाड़े निर्मम हत्या साफ बताती है कि उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरहद पर देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले ही आज अपने शहर में ही असुरक्षित हैं, आम नागरिक और कई समुदाय डर कर जीने को मजबूर हैं।''

उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, '' भाजपा राज में सिर्फ अपराधी बेखौफ और महफूज है। कभी शांति और सुरक्षा की पहचान रहा है हमारा उत्तराखंड, आज भाजपा के गैर-जिम्मेदार नेतृत्व में हिंसा, हत्या और भय के साये में सिमट कर रह गया है।'' उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी पूर्व सैन्य अधिकारी की मौत को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने

एक्स पोस्ट पर अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''देहरादून में मॉर्निंग वॉक के दौरान ब्रिगेडियर जोशी को गोली लगने की घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था का गंभीर संकेत है। एक समय था जब देहरादून और उत्तराखंड शांति और सुरक्षित माहौल के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन आज अपराधियों के बढ़ते हौसले उस छवि को कमजोर कर रहे हैं। राजपुर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और देर रात चल रही व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही। सरकार को चाहिए कि कानून-व्यवस्था पर तुरंत ठोस कदम उठाए और प्रदेश की सुरक्षा एवं शांति बहाल करे।''

बता दें कि राजधानी देहरादून के राजपुर पुलिस स्टेशन एरिया में रिटायर ब्रिगेडियर वीके जोशी की गोली लगने से मौत हो गई है। यह गोली उन्हें तब लगी जब वे सुबह टहलने के लिए निकले थे।

ईग्रामस्वराज से 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान

ग्रामीण डिजिटल गवर्नेंस को मिला बड़ा बढ़ावा

नई दिल्ली, आईएएनएस। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश की ग्राम पंचायतों ने ईग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक कुल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। साथ ही एआई-आधारित 'सभासार' मीटिंग टूल अब 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो गया है।

ईग्रामस्वराज के जरिए भुगतान सीधे वेंडर्स और सेवा प्रदाताओं को रियल-टाइम में किया जाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकती है। और यह प्लेटफॉर्म सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से जुड़ा हुआ है, जिससे पंचायत स्तर पर योजना, लेखांकन और खर्च की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है।

अधिकारियों ने बताया कि, इस सिस्टम ने नकद और कागज-आधारित पुराने तरीकों की जगह तेज, जवाबदेह और धोखाधड़ी से सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था को लागू किया है। जिससे, सरकार ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और समावेशी शासन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

देश की ग्राम पंचायतों में ईग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल गवर्नेंस में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं, एआई-आधारित 'सभासार' टूल ने वित्तीय पारदर्शिता और लोगों की भागीदारी को और भी मजबूत किया है।

वित्त वर्ष 2025-26 में पंचायत राज संस्थाओं

ने ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस के जरिए 53,342 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया और 2,55,254 ग्राम पंचायतों ने अपने विकास योजनाओं को इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया।

कुल मिलाकर 2,59,798 पंचायत राज संस्थाएं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं और 2,50,807 संस्थाओं ने वित्त वर्ष 2025-26 में ईग्रामस्वराज के जरिए ऑनलाइन भुगतान किया है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 1.6 करोड़ से ज्यादा वेंडर्स रजिस्टर्ड हैं।

'सभासार', जो एक वॉइस-टू-टेक्स्ट मीटिंग समरी टूल है, अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था और अब इसे 13 से बढ़ाकर 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। इसमें असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, संथाली और सिंधी जैसी भाषाएं भी शामिल की गई हैं ताकि ग्राम सभा की कार्यवाही स्थानीय भाषाओं में रिकॉर्ड की जा सके।

यह टूल मीटिंग की कार्यवाही, उपस्थिति, प्रस्ताव और फैसलों को ऑटोमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करता है, जिससे ग्राम सभा की प्रक्रिया ज्यादा आसान और भागीदारीपूर्ण बनती है।

पहले यह प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में उपलब्ध था। जैसे - हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू , लेकिन अब यह देश की भाषाई विविधता को पूरी तरह कवर करता है। जनवरी 2026 तक 1.11 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें इस प्लेटफॉर्म का उपयोग मीटिंग की जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए कर चुकी हैं, जो ग्रामीण डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

भारतीय नौसेना का युद्धपोत तारागिरी, तुरंत देगा खतरों का मुंहतोड़ जवाब

» **नई दिल्ली, आईएएनएस।**

भारतीय नौसेना को एक और नवीनतम स्टील्थ युद्धपोत, 'तारागिरी' मिलने जा रहा है। मंगलवार को साझा की गई एक जानकारी में नौसेना ने बताया कि इस युद्धपोत को 3 अप्रैल को कमीशन किया जाएगा।

विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युद्धपोत, 'तारागिरी' को नौसेना में शामिल करेंगे। यह युद्धपोत सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार कर सकती हैं। इसमें मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एक विशेष पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली भी है। अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन प्रणाली के चलते युद्धपोत का चालक दल पलक झपकते ही खतरों का जवाब दे सकता है। इन युद्धक क्षमताओं के साथ साथ तारागिरी मानवीय संकटों के समय आपदा राहत में भी बड़ी मदद कर

सकता है। इसकी अनुकूल मिशन प्रोफाइल इसे उच्च-तीव्रता वाले युद्ध से लेकर मानवीय सहायता और आपदा राहत तक हर चीज के लिए आदर्श बनाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह युद्धपोत एक बेहद शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। तारागिरी युद्धपोत 6,670 टन का है और इसमें स्वदेशी शिपयार्डों की परिष्कृत इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रतीक है।

मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा निर्मित यह युद्धपोत अपने पूर्ववर्ती डिजाइनों की तुलना में एक पीढ़ीगत विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इसके निर्माण में 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। गौरतलब है कि सोमवार 30 मार्च को ही भारतीय नौसेना में युद्धपोत, दूनागिरी शामिल किया गया है। यह एक बहुमुखी बहु-मिशन प्लेटफॉर्म हैं, जिन्हें समुद्री क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है।

दूनागिरी, पूर्व में भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा रहे लिएंडर श्रेणी के फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी का नवीनतम स्वरूप है। यह अत्याधुनिक फ्रिगेट नौसेना डिजाइन, स्टील्थ, मारक क्षमता, स्वचालन और उत्तरजीविता में अभूतपूर्व प्रगति का प्रतीक है। अन्य कई युद्धपोतों की तुलना में इसमें उन्नत हथियार और सेंसर लगे हैं।

जेएसडब्ल्यू समूह से टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को 421 करोड़ रुपये का ऑर्डर

20 मालगाड़ी रेक बनाएगी कंपनी

रेल लॉजिस्टिक्स में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी

» **डीएचएस ब्यूरो, नई दिल्ली।**

देश के रेलवे वैगन निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को जेएसडब्ल्यू समूह की कंपनियों से 421 करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी 20 रेक (मालगाड़ी वैगन) का निर्माण और आपूर्ति करेगी।

निजी फ्रेट वैगन सेक्टर में मजबूत पकड़

कंपनी को यह ऑर्डर लेटर ऑफ इंटेंट के रूप में मिला है, जो भारत के तेजी से बढ़ते निजी फ्रेट वैगन निर्माण क्षेत्र में टेक्समैको की मजबूत स्थिति को दशार्ता है। कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदीप्त मुखर्जी ने कहा कि यह ऑर्डर भारत में रेल आधारित लॉजिस्टिक्स के बढ़ते उपयोग को दशार्ता है और टेक्समैको इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को और मजबूत करेगा।

आधुनिक वैगनों का निर्माण

इस ऑर्डर के तहत कंपनी विभिन्न प्रकार के उन्नत वैगनों का निर्माण करेगी, जिनमें–बीएलसीएस वैगन, बीएलएसएस वैगन, बीएफएनवी वैगन और बीवीसीएम ब्रेक वैन शामिल हैं। ये वैगन विशेष रूप से कंटेनर आधारित माल परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स की क्षमता और दक्षता में सुधार होगा।

421 करोड़ का कुल ऑर्डर

इस परियोजना की कुल लागत लगभग 357.11 करोड़ (बिना जीएसटी) है, जबकि

जीएसटी सहित इसकी कुल कीमत 421.38 करोड़ है। यह ऑर्डर इस बात का संकेत है कि देश में रेल लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारतीय रेल की नीतियों के चलते उद्योग अब अधिक कुशल और किफायती परिवहन के लिए रेल नेटवर्क का उपयोग बढ़ा रहे हैं।

रेल आधुनिकीकरण में अहम भूमिका

टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड फ्रेट कार, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए देश के रेलवे आधुनिकीकरण और लॉजिस्टिक्स सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, एडवेंट्ज ग्रुप की प्रमुख कंपनी है और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। देशभर में इसकी सात निर्माण इकाइयां हैं और यह भारतीय रेलवे, निजी कंपनियों तथा निर्यात बाजारों को सेवाएं प्रदान करती है।

आज से लागू हो गए नए नियम: सैलरी, टोल टैक्स और रेल टिकट पर सीधा असर

» **नई दिल्ली, आईएएनएस।**

हर साल की तरह इस साल भी 1 अप्रैल से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। आज से इनकम टैक्स, आपकी सैलरी, रेल टिकट और बैंकिंग से जुड़े नियमों में फेरबदल हुआ है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। यहाँ उन 8 मुख्य बातों की जानकारी दी जा रही है जो आज से बदल गई हैं:

इनकम टैक्स का नया कानून

आज से 65 साल पुराना आयकर अधिनियम खत्म हो गया है और उसकी जगह 'नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025' लागू हो गया है। अब 'वित्तीय वर्ष' और 'आकलन वर्ष' का झंझट खत्म कर दिया गया है, अब इसे सीधा 'टैक्स वर्ष' कहा जाएगा। यानी आज से शुरू होने वाले समय को 'टैक्स वर्ष 2026-27' माना जाएगा। साथ ही, आईटीआर 3 और 4 भरने वालों के लिए तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है।

टोल प्लाजा पर कैश बंद

अगर आप आज गाड़ी लेकर हाईवे पर निकल रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज से देश के सभी टोल प्लाजा पर नगद (कैश) पैसे नहीं लिए जाएंगे। अब सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही भुगतान होगा। अगर आपके पास डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो आपको जुमार्ना भरना पड़ सकता है या वहां से वापस लौटाया जा सकता है।

घर आने वाली सैलरी में कमी

आज से नए लेबर कोड लागू हो सकते हैं। अब कंपनियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे आपकी बेसिक सैलरी (मूल वेतन) को कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत रखें। इससे आपका पीएफ ज्यादा कटेगा, जिससे हर महीने आपके हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन भविष्य के लिए आपकी बचत बढ़ जाएगी।

ग्रेच्युटी में होगा फायदा

लेबर कोड लागू होने से आपकी ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ जाएगी। चूंकि अब बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (डीए) का हिस्सा ज्यादा होगा, इसलिए नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी का लाभ पहले से बड़ा होगा। इसके अलावा, मकान किराया भत्ता की छूट के लिए अब मकान मालिक का पैन कार्ड देना जरूरी कर दिया गया है।

बंगाल चुनाव

भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा ने नक्सलवाद और राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कांग्रेस तथा विपक्षी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा अब न तो बंगाल में 'दीदी' रहेंगी, और न ही उत्तर प्रदेश में 'भैया' आएंगे। अगर दीदी संतुष्ट हैं, तो यह अच्छी बात है, लेकिन बंगाल की जनता असल में तभी खुश होगी, जब भाजपा सत्ता में आएगी।

देशहित संदेश 6
हर पन्ना जो बदले आपकी तकदीर
नई दिल्ली, बुधवार, 01 अप्रैल 2026

न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 90 लाख नाम हटाए जाने की संभावना

कोलकाता, आईएएनएस। चुनाव आयोग ने अनुमान लगाया है कि ह्लतार्किक विसंगतिह्व श्रेणी में रखे गए मतदाताओं के नामों को हटाने की प्रक्रिया के दौरान रोजाना जितनी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं, उसके आधार पर इस पूरी प्रक्रिया के अंत तक कुल हटाए गए नामों की संख्या 90 लाख से थोड़ी कम रह सकती है।

अंतिम अनुमानित विलोपन आंकड़े के निर्धारण को समझाते हुए मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में पहले ही कुल 63,66,952 नाम हटा दिए गए थे। ये नाम मुख्य रूप से 'मृत', 'स्थानांतरित', 'लापता' और 'डुप्लिकेट' मतदाताओं की श्रेणियों के तहत हटाए गए हैं।

सीईओ कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया, 'अंतिम मतदाता सूची में उन 60,00,675 मामलों को शामिल नहीं किया गया था, जिन्हें न्यायिक जांच के लिए भेजा गया था। अब, जहां तक न्यायिक प्रक्रिया का सवाल है, यह पाया गया है कि जिन मामलों का निपटारा हो चुका है, उनमें औसतन 40 से 45 प्रतिशत मामलों में नाम हटाए जा रहे हैं। इसी औसत दैनिक विलोपन दर के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि कुल हटाए गए नामों की अंतिम संख्या लगभग 90 लाख के आसपास रहेगी।'

सूत्र ने आगे कहा कि यह अनुमानित आंकड़ा न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में नाम हटाए जाने की औसत दैनिक दर पर आधारित है। न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में जिन मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, उन्हें इस उद्देश्य के लिए गठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में से किसी में भी जाने का अवसर मिलेगा। फिलहाल, सोमवार रात तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगभग 16 लाख मतदाताओं के लिए न्यायिक निर्णय प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और आयोग को विश्वास है कि यह प्रक्रिया इसी सप्ताह पूरी हो जाएगी। वर्तमान में, 700 से अधिक न्यायिक अधिकारी, जिनमें पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड से 100-100 अधिकारी शामिल हैं, इस निर्णय प्रक्रिया में लगे हुए हैं और वे इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। पहले चरण में 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा। परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी सूची, कई नामों को मिली मंजूरी

कोलकाता, आईएएनएस। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें कई अहम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। जारी सूची के अनुसार, सिताई (एससी) विधानसभा से आशुतोष बर्मा को टिकट दिया गया है, जबकि नाटाबाड़ी सीट से गिरिजा शंकर रॉय चुनाव मैदान में होंगे। बागदा (एससी) से सोमा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मगराहाट पूर्व (एससी) सीट से उत्तम कुमार बनिक को मौका मिला है।

फालटा सीट से देबांगशु पांडा और सोनारपुर उत्तर से देबाशीष धर को उम्मीदवार घोषित किया गया है। चौरंगी सीट से संतोष पाठक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हावड़ा दक्षिण सीट से रंजन कुमार पॉल और पंचला से श्यामल हाती को टिकट मिला है। इसके अलावा चंडीपुर से डॉ. पीयूष कांति दास, गारबेटा से प्रदीप लोढ़ा, मेमारी से मानव गुहा और बाराबनी सीट से अरिजीत रॉय को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में भी एक अहम बदलाव किया है। मयनागुड़ी (एससी) सीट से अब दालिम रॉय को उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी का कहना है कि इन सभी नामों पर गहन विचार-विमर्श के बाद मुहर लगाई गई है। भाजपा आगामी चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय समीकरण और संगठन की मजबूती को ध्यान में रखा गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे जबकि दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं, वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी और चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

ममता का चुनाव आयोग पर मतदाता सूची हेरफेर का गंभीर आरोप

कोलकाता, आईएएनएस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत कर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है।

ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा है, यह अत्यंत चिंता का विषय है कि भारत निर्वाचन आयोग जैसा संवैधानिक प्राधिकरण बंगाल की जनता के लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों को कमजोर करता प्रतीत हो रहा है। त्रुटिपूर्ण और लक्षित प्रतीत होने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया ने लाखों लोगों को गंभीर कठिनाई में डाल दिया है, जिससे कई लोग मताधिकार से वंचित होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इस प्रक्रिया में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई है। यह अत्यंत दुखद है कि ऐसी घटनाओं के बावजूद भी निर्वाचन आयोग ने अधिक मानवीय और उत्तरदायी दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। पत्र में आगे लिखा है, अब हम भाजपा द्वारा निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने के एक और समन्वित प्रयास को देख रहे हैं। विश्वसनीय रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भाजपा के एजेंटों द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और कई जिलों में बड़ी संख्या में फॉर्म 6 आवेदन जमा किए जा रहे हैं। ये मतदाता सूची में गैर-निवासियों को शामिल करने की एक शरारती चाल प्रतीत नहीं होती हैं। इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं हैं कि ये आवेदन उन व्यक्तियों से संबंधित हो सकते हैं जो बंगाल के वास्तविक निवासी नहीं हैं और जिनका राज्य से कोई वैध संबंध नहीं है। इसी तरह के मामले बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनावों से पहले भी देखे गए थे। यदि ये बातें सच हैं, तो ऐसे कृत्य अवैध, असंवैधानिक और मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक होंगे, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे और कुटिल मंशा को दशार्ते हैं। यह किसी संवैधानिक प्राधिकरण से अपेक्षित मानक नहीं है। जनता को पारदर्शिता और अपने मतदान अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार है।

ममता बनर्जी ने कहा, ₹सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त निदेर्शों से स्पष्ट है कि अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाने या हटाए जाने से संबंधित दावों और आपत्तियों का निपटारा न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की गई थी। इस सूची में लगभग 60 लाख मामलों को विचाराधीन रखा गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेर्शों के अनुरूप दावे और आपत्तियां दोनों शामिल हैं। इसके बाद, विचाराधीन कार्यवाही अभी भी जारी है, और चुनाव आयोग द्वारा अब तक चार पूरक सूचियां प्रकाशित की जा चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील के लिए एक तंत्र भी निर्धारित किया है और जो लोग निर्णय से असंतुष्ट हैं वे अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के कारण अंतिम मतदाता सूची तैयार करने के मामले में असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया है।

कोर्ट के बाद अब सियासत में पेस, JP जॉइन कर शुरू की नई पारी

डीएचएस ब्यूरो

नई दिल्ली। लिएंडर पेस ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रही। लिएंडर पेस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे सम्मान मिल चुके हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया है।

नेताओं की मौजूदगी में शामिल हुए

इस अवसर पर किरेन रिजिजू, सुकांत मजूमदार और अरुण सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नेताओं ने पेस के पार्टी में शामिल होने को महत्वपूर्ण बताया।

बंगाल और देश के लिए अहम कदम

सुकांत मजूमदार ने कहा कि लिएंडर पेस का भाजपा में शामिल होना पश्चिम बंगाल और देश के लिए गर्व की बात है। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। किरेन

रिजिजू ने कहा कि लिएंडर पेस हमेशा से युवाओं के लिए प्रेरणा रहे हैं और अब वे राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

खेल और युवाओं पर रहेगा फोकस

भाजपा में शामिल होने के बाद पेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे देश में खेलों के विकास और युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए काम करेंगे। लिएंडर पेस ने कहा कि देश में खेल सुविधाओं को मजबूत करना जरूरी है।

दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग में पंचकोणीय मुकाबला

कोलकाता, आईएएनएस। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अधिकांश पर अगले महीने दो चरणों में मतदान होने जा रहा है, जहां चार-कोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग की तीन पहाड़ी सीटों पर पंचकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। अधिकांश विधानसभा सीटों पर चार प्रमुख उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), सीपीआई-एम के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा और अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा (एआईएसएफ) गठबंधन और कांग्रेस हैं। हालांकि, कुर्सियांग, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग में चुनावी मुकाबला स्पष्ट रूप से पंचकोणीय होगा।

इन तीन पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्रों में, मुख्य चुनावी दलों में भाजपा (बिमल गुरुंग द्वारा स्थापित गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जीजेएम), अनित थापा द्वारा स्थापित भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, अजय एडवर्ड्स द्वारा स्थापित भारतीय गोरखा जनशक्ति मोर्चा, आईजीजेएफ, वाम मोर्चा-एआईएसएफ गठबंधन और कांग्रेस शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आईजीजेएफ द्वारा स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार उतारकर चुनावी मैदान में उतरने से जीजेएम

समर्थित भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थित बीजीपीएम, दोनों के लिए समीकरण जटिल हो गए हैं, खासकर दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग में, जहां गोरखा मतदाता चुनावी परिणामों को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर सभी प्रतिद्वंद्वी दलों का दावा है कि आईजीजेएफ के प्रवेश से इन निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी जीत आसान हो गई है। एक तरफ, भाजपा और उसके पहाड़ी सहयोगी जीजेएम का तर्क है कि चूंकि आईजीजेएफ को पहाड़ियों में भाजपा विरोधी ताकत के रूप में देखा जाता है, इसलिए उसके उम्मीदवार भाजपा विरोधी और जीजेएम विरोधी गोरखा वोट बैंक में सेंध लगाएंगे।

भाजपा का संकल्प पत्र: असम में 2 लाख अतिरिक्त सरकारी नौकरियां, 64 लाख भर्तियों का वादा

भगवा पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए वादों की झड़ी लगाते हुए जारी किया संकल्प पत्र

गुवाहटी, आईएएनएस। असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में 64 लाख भर्तियों के अलावा 2 लाख अतिरिक्त सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का वादा किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर असम अभियान के तहत 10 लाख युवाओं को नए उद्यम स्थापित करने में सहायता के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। नए स्नातकों को नौकरी की तैयारी के लिए 25,000 रुपए प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की जीवन प्रेरणा योजना को जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के तहत 22 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं, ऐसे में प्रत्येक परिवार को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त 15 लाख मकानों का निर्माण करने का भी संकल्प है। निर्बाध और समयबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक असम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एकीकृत अवसंरचना में 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा सरसों तेल, चावल, मसूर दाल, चीनी और नमक रियायती दर पर उपलब्ध कराना

जारी रखेंगे। साथ ही सबसे गरीब परिवारों को मुफ्त राशन भी देने की घोषणा की है।

इसके अलावा संकल्प पत्र में मौजूदा लाभार्थियों को दूसरे चरण में 25,000 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का विस्तार करके 40 लाख लाभार्थियों को लाभ देंगे। ओरुनोदोई योजना के तहत मासिक सहायता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 23,000 हजार किया जाएगा, जिससे अतिरिक्त 15 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। मिशन बसुंधरा के तहत अवैध अप्रवासियों द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि के हर इंच को मुक्त करने और असम के सभी वास्तविक नागरिकों को भूमि अधिकार प्रदान करेंगे। गरीबों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और निजुत मोइना, निजुत बाबू, शुल्क माफी, मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा और मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरण योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।

अवैध अप्रवासियों के खिलाफ वापसी की नीति जारी रखने और लव जिहाद और लैंड जिहाद की समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाएं जाएंगे। असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बाढ़ मुक्त असम मिशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा ने सभी पात्र चाय बागान परिवारों को भूमि पट्टे उपलब्ध कराने और चरणबद्ध तरीके से मजदूरी बढ़ाकर 500 करना सुनिश्चित करेंगे।

भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा है, हम 'एक जिला, एक विश्वविद्यालय' पहल शुरू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों का व्यापक कवरेज हो ताकि असम में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। हम असम में शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाएंगे। शिक्षकों की संख्या, गरीबों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करना और निजुत मोइना, निजुत बाबू, शुल्क माफी, मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा और मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता जारी रखेंगे।

केरल में सत्ता परिवर्तन तय, जनता ने बना लिया है मन : एके एंटनी

तिरुवनंतपुरम, आईएएनएस। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन अब तय है और जनता पहले ही अपना मन बना चुकी है। केरल में 9 अप्रैल को 140 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। एके एंटनी ने कहा, ₹केरल की जनता अपने दिल में पहले ही वोट दे चुकी है।₹ उन्होंने भरोसा जताया कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) जोरदार वापसी करेगा। बिजली की गड़गड़ाहट की तरह यूडीएफ वापसी करेगा। जनता ने तय कर लिया है कि इस सरकार को जाना ही होगा। उन्होंने मौजूदा शासन को महज एक 'कार्यवाहक सरकार' बताया।

तीन बार के मुख्यमंत्री रह चुके एंटनी अब सक्रिय राजनीति से दूर हैं लेकिन वह रोजाना पार्टी मुख्यालय पहुंचकर लोगों से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर निशाना साधते हुए एंटनी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आम जनता के लिए 'अदृश्य' हो गए हैं और लोगों से मिलने-जुलने से बचते हैं। उन्होंने राज्य सचिवालय की तुलना 'रावण के किले' से करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आलोचना बर्दाश्त नहीं करते।

एंटनी ने कहा कि यूडीएफ को ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विजयन सरकार का लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का विचार ही मतदाताओं को उनके खिलाफ कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। उन्होंने कहा कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने का विचार ही जनता को चौंका रहा है। एंटनी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समर्थन दे दें, तब भी जनता तीसरी बार विजयन सरकार को स्वीकार नहीं करेगी। राज्य की बदलती राजनीति पर टिप्पणी करते हुए एंटनी ने कहा कि पहले असंतोष कांग्रेस के भीतर देखने को मिलता था लेकिन अब स्थिति उलट गई है और वामपंथी समर्थक ही सरकार से दूर हो रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केरल में उसका ज्यादा राजनीतिक प्रभाव नहीं है और वह अप्रत्यक्ष रूप से सीपीआई(एम) को फायदा पहुंचाती है। एंटनी ने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती कि राज्य में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने।

भाजपा ने जारी किया घोषणापत्र; एम्स, मेट्रो और हाई-स्पीड कॉरिडोर का वादा

तिरुवनंतपुरम, आईएएनएस। भाजपा ने मंगलवार को केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में पार्टी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कल्याणकारी उपायों के एक महत्वाकांक्षी मिश्रण की रूपरेखा प्रस्तुत की।

चुनावी घोषणापत्र में केरल में एक एम्स स्थापित करने, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने और तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक एक हाई-स्पीड कॉरिडोर लागू करने का वादा किया गया है। आश्वासनों में गरीब

परिवारों के लिए सालाना दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, हर महीने प्रति घर 20 हजार लीटर मुफ्त पीने का पानी और पेंशन को बढ़ाकर 3 हजार रुपए करना शामिल है। इसके अलावा, पार्टी ने देवस्वम बोर्डों का पुनर्गठन करने और सबरीमाला सोने की तस्करी मामले में सीबीआई जांच शुरू करने का भी संकल्प लिया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने यह घोषणापत्र जारी किया। इस अवसर पर केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए।भाजपा ने 2016 में नेमोम से वरिष्ठ नेता ओ राजगोपाल के जरिए अपनी एकमात्र विधानसभा सीट जीती थी। हालांकि, 2021 में एक कड़े त्रिकोणीय मुकाबले में सीपीआई-एम के वी शिवनकुट्टी ने यह विधानसभा सीट फिर से हासिल कर ली। शिवनकुट्टी अब इस सीट को अपने पास बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर विधानसभा चुनावों की घोषणा से काफी पहले ही अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिससे भाजपा के अपने खोए हुए राजनीतिक आधार को फिर से हासिल करने के इरादे का संकेत मिला। **आईएएनएस**

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का एसडीपीआई से गठजोड़ से इनकार

तिरुवनंतपुरम, आईएएनएस। आगामी केरल विधानसभा चुनाव से पहले पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए सीपीआई(एम)-एसडीपीआई गठजोड़ के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि न तो एसडीपीआई से किसी तरह का समर्थन मांगा गया है और न ही उनके साथ किसी प्रकार की कोई समझ है। उन्होंने कहा कि नेमोम सीट की स्थिति पहले जैसी ही है और 2021 विधानसभा चुनाव से इसकी तुलना करना गलत है। सीएम विजयन ने कहा, ₹कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एलडीएफ सबसे बेहतर विकल्प है, लेकिन इसे किसी राजनीतिक समझौते के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने दोहराया कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की विचारधारा पूरी तरह से स्पष्ट है और वह किसी भी तरह के सांप्रदायिक रुख के खिलाफ सख्ती से खड़ा है। इस दौरान उन्होंने कोल्लम में सोमवार को हुए एक विवाद का भी जिक्र किया, जहां मीडिया से उनकी बातचीत को लेकर आलोचना हुई थी।

एलएसजी के सामने होगी डीसी की चुनौती, जानें पिच और मौसम का हाल

नई दिल्ली, आईएएनएस। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें सीजन में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स अपने अभियान का आगाज लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ करेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाना है। अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली सीजन का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी। वहीं, एलएसजी भी अपने घरेलू मैदान पर दमदार प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछला सीजन मिलाजुला रहा था। शुरूआत में टीम ने दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन दूसरे हाफ में टीम की गाड़ी जीत की पटरी से उतर गई थी। कागज पर दिल्ली आईपीएल 2026 में भी काफी दमदार दिख रही है। सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम के पास केएल राहुल जैसा अनुभवी बल्लेबाज मौजूद है, जिनका साथ पृथ्वी शॉ देते हुए नजर आ सकते हैं। अभिषेक पोरेल ने पिछले सीजन अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया था और 146 के स्ट्राइक रेट से 301 रन बनाए थे। करुण नायर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल और नीतीश राणा की मौजूदगी में टीम का मध्यक्रम भी संतुलित नजर आ रहा है। डेविड मिलर के आने से टीम के बल्लेबाजी क्रम को और मजबूती मिली है।

समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा और विपराज निगम दिल्ली की ओर से फिनिशर की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, शुरूआती मुकाबलों में मिचेल स्टार्क की गैरमौजूदगी जरूर टीम को खल सकती है। स्टार्क के ना होने पर तेज गेंदबाजी की कमान लुंगी एनगिडी या दुष्मंत चमीरा के हाथों में सौंपी जा सकती है, जिनका साथ मुकेश कुमार और टी नटराजन देते हुए नजर आएंगे। स्पिन विभाग की कमान कुलदीप यादव और अक्षर पटेल संभालेंगे।

६ दूसरी ओर, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और एडेन मार्करम की मौजूदगी में लखनऊ सुपर जायंट्स का टॉप ऑर्डर दमदार दिख रहा है। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी कप्तान ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, शाहबाज अहमद, और अब्दुल समद के ऊपर होगी।

वानिंदु हसरंगा की फिटनेस पर अभी सवाल है और उन्हें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है। हालांकि, लखनऊ के गेंदबाजी अटैक में इस सीजन दम दिख रहा है। मोहम्मद शमी के साथ नई गेंद का आगाज मयंक यादव या फिर एनरिक नॉर्टजे करते हुए दिख सकते हैं।

एक अप्रैल को जन्मे दो दिग्गज भारतीय, खेल जगत में किया नाम रोशन

नई दिल्ली, आईएएनएस। भारतीय खेल जगत के लिए 'एक अप्रैल' का दिन बेहद खास है। इसी दिन 2 ऐसी हस्तियों का जन्म हुआ, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। आइए, इनके बारे में जानते हैं।

फौजा सिंह: 1 अप्रैल 1911 को पंजाब के जालंधर में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसान परिवार में यह बालक चार बच्चों में सबसे छोटा था, जिसका नाम रखा गया फौजा सिंह। पांच साल की उम्र तक फौजा चलने में सक्षम नहीं थे, पैर बेहद कमजोर थे, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों का डटकर सामना किया।

परिवार को समर्थन देने के लिए फौजा सिंह ने खेती शुरू की। साल 1992 में फौजा सिंह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बेटे के साथ लंदन में बस गए। साल 1994 में जब उनके पांचवें बेटे कुलदीप की मृत्यु हुई, तो इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने टहलना शुरू किया और धीरे-धीरे यह चहलकदमी दौड़ में बदल गई।

साल 2000 तक फौजा सिंह ने दौड़ को गंभीरता से नहीं लिया था। 89 साल की उम्र में उन्होंने 6 घंटे 54 मिनट में फुल मैराथन को पूरा किया। साल 2003 में टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन में '90 से अधिक' श्रेणी में पांच घंटे 40 मिनट में दौड़ पूरी की।

'टरबैन्ड टोनेडो' के नाम से मशहूर फौजा सिंह ने साल 2011 में 100 वर्ष की उम्र में कनाडा के टोरंटो के बिर्चमाउंट स्टेडियम में विशेष ओंटारियो मास्टर्स एसोसिएशन आमंत्रण मीट में एक ही दिन में आठ विश्व आयु समूह रिकॉर्ड बनाए।

फौजा सिंह ने 100 मीटर दौड़ 23.14, 200 मीटर दौड़ 52.23, जबकि 400 मीटर दौड़ 2:13.48 में पूरी की। इसके अलावा, 800 मीटर दौड़ 5:32.18 और 1500 मीटर दौड़ 11:27.81 में पूरी की। एक मील दौड़ 11:53.45, 3000 मीटर दौड़ 24:52.47 और 5000 मीटर दौड़ 49:57.39 समय में पूरी की।

फौजा सिंह लंदन 2012 ओलंपिक के लिए एक टॉर्च बियरर रहे, उन पर 'टरबैन्ड टोनेर्ड' नामक एक किताब लिखी गई। 14 जुलाई 2025 को 114 साल की उम्र में फौजा सिंह एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें उनका निधन हो गया।

एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रिया की शानदार जीत

» **उलानबटार, आईएएनएस।**

एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत की प्रिया ने 5:0 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि जादुमणि सिंह ने टॉप सीड बॉक्सर को मुकाबले के आखिर तक कड़ी टक्कर दी।

महिलाओं की 60 किलोग्राम कैटेगरी में, प्रिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान की रिम्मा वोलोसेंको को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। पूरे मुकाबले के दौरान उन्होंने गजब का नियंत्रण और संयम दिखाया, जिसके दम पर वह अगले दौर में पहुंच गईं।

अगले मुकाबले में उनका सामना चीन की चेंग्यू यांग से होगा, जो इस कैटेगरी की दूसरी वरीयता प्राप्त बॉक्सर हैं। यह मुकाबला काफी रोमांचक और उच्च स्तर का होने की उम्मीद है।

पुरुषों की 55 किलोग्राम कैटेगरी में, जादुमणि ने जापान के रुई यामागुची के खिलाफ कड़ा मुकाबला लड़ा, लेकिन आखिर में उन्हें 2-3 के स्प्लिट डिसीजन से हार का सामना करना पड़ा। यामागुची इस कैटेगरी के शीर्ष वरीयता प्राप्त बॉक्सर हैं और वह इस टूनार्मेंट में मजबूत दावेदार के तौर पर उतरे थे। उनके नाम अस्ताना इवेंट में रजत पदक और बॉक्सिंग विश्व कप फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जैसी बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं।

इतने अनुभवी और सफल प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के बावजूद, जादुमणि ने उन्हें हर पंच का करारा जवाब दिया। उन्होंने मुकाबले को आखिरी पल तक रोमांचक बनाए रखा और यह दिन के सबसे करीबी मुकाबलों में से एक साबित हुआ। शानदार प्रदर्शन और कड़े संघर्षों के मेल के साथ, भारतीय दल टूनार्मेंट के शुरूआती चरणों में अपना अभियान जारी रखे हुए है।

एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में पूरे महाद्वीप से शीर्ष मुक्केबाजी प्रतिभाएं हिस्सा ले रही हैं। इस टूनार्मेंट का हर मुकाबला मेडल राउंड तक पहुंचने की राह तय करने में अहम भूमिका निभाता है।

पहले दिन, भारत की प्रीति पंवार और दीपक ने शानदार शुरूआत की थी। महिलाओं की 54 किलोग्राम कैटेगरी में, विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल की स्वर्ण पदक विजेता प्रीति ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान की एलिना बाजारोवा को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। एलिना बाजारोवा 2025 की एशियाई अंडर-22 चैंपियन रह चुकी हैं। पुरुषों की 70 किलोग्राम कैटेगरी में, दीपक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान के खावासबेक असादुल्लायेव को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से कड़े मुकाबले में हरा दिया।

विश्व की नंबर एक महिला बल्लेबाज बनीं वोल, मूनी को पछाड़ा

दुबई, आईएएनएस। ऑस्ट्रेलिया की युवा बल्लेबाज जॉर्जिया वोल आईसीसी की जारी ताजा टी20 रैंकिंग में दुनिया की नंबर एक बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने बेथ मूनी की 26 महीने से जारी बादशाहत को खत्म कर दिया है। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में जॉर्जिया वोल का प्रदर्शन दमदार रहा था। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी तीसरे नंबर पर खिसक गई हैं।

इस टी20 सीरीज के दौरान जॉर्जिया वोल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने टी20 करियर का पहला शतक भी लगाया था। उन्होंने 52 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी। जॉर्जिया ने ताजा रैंकिंग में 8 पायदान की छलांग लगाई है। वोल के अब 815 रेटिंग प्वाइंट्स हो गए हैं और वह बेथ मूनी से आगे निकल गई हैं। मूनी दूसरे नंबर पर खिसक गई हैं और उनके 788 रेटिंग प्वाइंट्स हैं। भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को भी एक पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है और वह अब तीसरे नंबर आ गई हैं। वहीं, हेली मैथ्यूज चौथे नंबर पर खिसक गई हैं।

बेथ मूनी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में जनवरी 2024 से विश्व की नंबर एक बल्लेबाज बनी हुई थीं। उन्होंने ताहिला मैक्ग्रा से नंबर एक की पोजीशन को छीना था। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में जॉर्जिया वोल ने अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था। उन्होंने 3 मुकाबलों में 172 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 148 रन बनाए थे। जॉर्जिया के दमदार प्रदर्शन के बूते ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम करने में सफल रही थी।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करने वालीं न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अमेलिया केर दुनिया की नंबर एक ऑलराउंडर बन गई हैं।

उनके कुल 508 रेटिंग प्वाइंट्स हो गए हैं और उन्होंने वेस्टइंडीज की स्टार खिलाड़ी हेली मैथ्यूज को नंबर 2 पर ढकेल दिया है। केर यह मुकाम हासिल करने वाली न्यूजीलैंड की महज चौथी खिलाड़ी हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि सिर्फ रेबेका स्टील, एमी वॉटकिंस और सोफी डिवाइन ही हासिल कर सकी हैं। हेली मैथ्यूज अक्टूबर 2023 से दुनिया की नंबर एक ऑलराउंडर बनी हुई थीं।

मैडी ग्रीन अपनी टीम की हार में 85 रन बनाने के बाद बल्लेबाजों की रैंकिंग में चार पायदान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर आ गई हैं।

वनडे रैंकिंग में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दो एकदिवसीय मुकाबले में कोई खास प्रदर्शन न करने की वजह से अलाना किंग गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे पायदान पर खिसक गई हैं। इंग्लैंड की गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन विश्व की नंबर एक वनडे गेंदबाज बन गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वेयरहम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दो वनडे में 81 रन बनाने और चार विकेट लेने के बाद ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में आठ पायदान ऊपर चढ़कर 16वें स्थान पर आ गई हैं।

अगले स्तर पर जाने को तैयार वैभव

नई दिल्ली, आईएएनएस। आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने वैभव की जमकर तारीफ की है। कैफ वैभव की चेन्नई के खिलाफ खेली गई अर्धशतकीय पारी से खासा प्रभावित नजर आए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा, 'पिछले सीजन में मुझे लगा था कि वैभव सूर्यवंशी को बहुत जल्दी हाइप मिल रही है। एक पुराने जमाने का क्रिकेटर होने के नाते, मेरा मानना है कि युवा खिलाड़ियों को तेजी से आगे बढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि, एक साल बाद, मुझे लगता है कि वह अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। 15 साल का यह लड़का मनोरंजन कर सकता है और मैच जिताने वाली पारियां खेल सकता है।'

वैभव सूर्यवंशी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बेहतरीन लय में दिखाई दिए। वैभव ने पावरप्ले में ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी से फैंस का खूब मनोरंजन किया। वैभव ने अपना अर्धशतक सिर्फ 15 गेंदों में पूरा किया। वह आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। वैभव ने 17 गेंदों का सामना करते हुए 52 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के लगाए। वैभव ने यशस्वी जायसवाल के साथ पहले विकेट के लिए सिर्फ 6.2 ओवर में 75 रन जोड़े। वैभव की दमदार पारी के बूते राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई से मिले 128 रनों के लक्ष्य को महज 12.1 ओवर में हासिल कर लिया। यशस्वी 36 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ध्रुव जुरैल ने 18 रनों का योगदान दिया। आईपीएल 2025 में भी वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान खींचा था।

सीजन के अंत में बायर्न म्यूनिख से अलग होंगे राफेल गुएरेरो

> ❑ बायर्न के स्पोर्ट मेंबर मैक्स एबरल ने गुएरेरो की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 'हम राफेल को उस समय के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने हमारे साथ बिताया। आप मैदान पर हमेशा राफेल पर भरोसा कर सकते हैं, और उनके जैसे खिलाड़ी किसी भी ड्रेसिंग रूम को बेहतर बनाते हैं।'

बर्लिन, आईएएनएस। पुर्तगाल के इंटरनेशनल खिलाड़ी राफेल गुएरेरो बार्यन म्यूनिख फुटबॉल क्लब से इस सीजन के खत्म होने के बाद अलग हो जाएंगे। गुएरेरो का कॉन्ट्रैक्ट भी इस सीजन के अंत में ही खत्म हो रहा है। गुएरेरो और क्लब ने इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। गुएरेरो साल 2023 में बोरूसिया डॉर्टमुंड से फ्री ट्रांसफर पर बायर्न म्यूनिख में आए थे। उन्होंने बायर्न के लिए कुल 89 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 12 गोल किए और 8 गोल करने में मदद (असिस्ट) की। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह रही कि वे एक ही पोजीशन तक सीमित नहीं थे। वे डिफेंस में फुल-बैक के रूप में भी खेले और जरूरत पड़ने पर मिडफील्ड में भी योगदान दिया। इसी वजह से वह टीम के एक बहुमूल्य खिलाड़ी रहे। गुएरेरो ने टीम को कई खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया। उन्होंने बायर्न के साथ बुंडेसलीगा का खिताब और जर्मन सुपर कप जीता। इसके अलावा, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम पुर्तगाल के लिए भी 65 मैच खेले हैं। बायर्न के स्पोर्ट मेंबर मैक्स एबरल ने गुएरेरो की जमकर तारीफ की।

उन्होंने कहा, 'हम राफेल को उस समय के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने हमारे साथ बिताया। आप मैदान पर हमेशा राफेल पर भरोसा कर सकते हैं, और उनके जैसे खिलाड़ी किसी भी ड्रेसिंग रूम को बेहतर बनाते हैं।' उन्होंने कहा कि राफेल और क्लब के बीच बातचीत सकारात्मक और सम्मानजनक तरीके से हुई। 'उनके साथ हमारी बातचीत सकारात्मक रही है, जो भरोसे और आपसी समझ पर आधारित है। अब उनके साथ मिलकर हम गर्मियों तक अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे रहे हैं। हम अभी भी साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं।' अब गुएरेरो और बायर्न म्यूनिख, दोनों ही इस सीजन के बाकी मैचों पर ध्यान दे रहे हैं। टीम इस समय लीग में पहले स्थान पर है और दूसरे नंबर की टीम से 9 अंकों से आगे है।

मियामी ओपन जीतकर लाइव रैंकिंग में अल्काराज के करीब पहुंचे सिनर

लंदन, आईएएनएस। जैनिक सिनर ने इंडियन वेल्स मास्टर्स और मियामी ओपन जीतकर 'सनशाइन डबल' पूरा किया। इसके बाद वह लाइव रेस में अपने बड़े प्रतिद्वंद्वी कार्लोस अल्काराज के करीब पहुंच गए, जहां दोनों खिलाड़ियों के बीच सिर्फ 50 अंकों का अंतर रह गया।

अल्काराज ने साल की शुरूआत ऑस्ट्रेलियन ओपन और दोहा के एटीपी 500 खिताब जीतकर की थी, जिससे उनकी 16 मुकाबलों की जीत की लय बनी, जो इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में जाकर टूटी। इसके बाद सिनर ने शानदार फॉर्म पकड़ी और 'सनशाइन डबल' जीतकर जोरदार वापसी की। एटीपी ईयर-एंड नंबर 1 की दौड़ में अल्काराज और सिनर सबसे आगे हैं, जिनके पास क्रमशः 2,950 और 2,900 रैंकिंग अंक हैं। 'एटीपी' की रिपोर्ट के अनुसार, कोई भी अन्य खिलाड़ी इन दोनों से 1,000 अंकों के दायरे में नहीं है। तीसरे स्थान पर मौजूद डेनिल मेदवेदेव अभी सिनर से 1,200 अंक पीछे हैं। इस बीच, आर्थर फिल्स और जिरी लेहेका ने मियामी में अपने करियर की नई ऊंचाइयां छूते हुए एटीपी फाइनल्स के लिए पहली बार क्वालीफाई करने की अपनी कोशिश जारी रखी है।

हम बल्लेबाजी में बेहतर कर सकते थे: ऋतुराज

» **गुवाहाटी, आईएएनएस।**

आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने माना है कि बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन की वजह से टीम को हार झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे।

मैच के बाद कप्तान ऋतुराज ने कहा, 'मुझे लगा कि शुरू में हालात बहुत मुश्किल थे, खासकर आर्चर और बर्गर का सामना करते समय। उन्होंने शानदार लेंथ पर गेंदबाजी की। आपने देखा कि पिच से स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिल रही थी। हां, हम बल्लेबाजी में बेहतर कर सकते थे। हम मुकाबले को और आगे ले जा सकते थे। बल्लेबाजी में अगर हम कुछ स्किल दिखाते, तो शायद 150 से 160 रनों के स्कोर तक पहुंच सकते थे।

हालांकि, आजकल आप नहीं जानते हैं कि अच्छा स्कोर क्या हो सकता है। ऐसे में आपको बस रन बनाते जाना होता है। मुझे लगता है कि यह उन दिनों में से एक था जब विकेट थोड़ा मुश्किल था। हालांकि, मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं।'

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। संजू सैमसन 7 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 रन ही बना सके, जबकि कप्तान ऋतुराज भी 6 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। आयुष म्हात्रे बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, तो मैथ्यू शॉर्ट 2 रन ही बना सके। सरफराज खान 12 गेंदों में 17 रन बनाने के बाद जडेजा का शिकार बने। युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने 18 रन बनाए। शिवम दुबे भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 6 रन बनाकर आउट हुए। जेमी ओवरटन ने टीम की ओर से 36 गेंदों में सर्वाधिक 43 रन बनाए, जिसके बूते चेन्नई की टीम 100 रनों का आंकड़ा पार करने में सफल रही।

> ❑ टीम के गेंदबाज भी लय में दिखाई नहीं दिए। मैट हेनरी ने 3 ओवर में 40 रन दिए, जबकि नूर अहमद ने 2 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 24 रन खर्च किए। हालांकि, अंशुल कंबोज अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट निकाले।

ओवरटन ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए। चेन्नई के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार करने में नाकाम रहे। टीम के गेंदबाज भी लय में दिखाई नहीं दिए।

मैट हेनरी ने 3 ओवर में 40 रन दिए, जबकि नूर अहमद ने 2 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 24 रन खर्च किए। हालांकि, अंशुल कंबोज अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट निकाले। आईपीएल 2026 में चेन्नई अपने अगले मुकाबले में 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स से भिड़ेगी।

कहानी विदेशी जमीं पर पहली टेस्ट सीरीज जिताने वाले भारतीय कप्तान की

नई दिल्ली, आईएएनएस। अजीत वाडेकर, भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा कप्तान जिन्होंने देश को विदेशी सरजमीं पर जीतने का हुनर सिखाया। अजीत ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम में वो जज्बा जगाया, जिसके बूते टीम ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का पहली बार किला भेदा। वाडेकर जितने अच्छे कप्तान थे, उतने ही शानदार बल्लेबाज भी रहे। वाडेकर की क्रिकेट की दुनिया में आने की कहानी भी काफी दिलचस्प है।

अजीत वाडेकर का जन्म एक अप्रैल 1941 को मुंबई में हुआ। अजीत पढ़ाई में काफी अच्छे थे और वह इंजीनियर बनना चाहते थे। अजीत का दूर-दूर तक क्रिकेट से कोई नाता नहीं था। हालांकि, प्रतिदिन 3 रुपये कमाने की चाहत ने उन्हें पहली बार मैदान पर उतारा और उसके बाद जो हुआ, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दरअसल, भारत के पूर्व क्रिकेटर बालू गुप्ते कॉलेज में अजीत के सीनियर हुआ करते थे। बालू कॉलेज टीम की तरफ से खेला करते थे और उन्होंने अजीत को 12वें खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल होने का ऑफर दिया था।

कॉलेज टीम की प्लेइंग इलेवन तो दमदार थी लेकिन उनके पास पानी पिलाने के लिए कोई खिलाड़ी नहीं था और इसके लिए अजीत वाडेकर को चुना गया। अजीत को प्रतिदिन के लिए 3 रुपए दिए जाते थे। वाडेकर को 22 गज की पिच पर खेला जाने वाला यह खेल पसंद आने लगा और उन्होंने भी कॉलेज की टीम से खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अजीत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए अपना डेब्यू साल 1966 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया। उस दौर में विदेशी सरजमीं पर एक मैच तक जीतना भारतीय टीम के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। अजीत की बल्लेबाजी में दमखम को देखते हुए उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। साल 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारतीय टीम वेस्टइंडीज गई और इतिहास रचकर वतन लौटी। अजीत की अगुवाई में भारतीय टीम ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया।

ईरान के लोग हवाई हमलों को ट्रैक करने के लिए इस ऐप का कर रहे इस्तेमाल

तेहरान। ईरान में 30 दिनों से ज्यादा समय तक इंटरनेट बंद है। ईरानी लोग हवाई हमलों और जरूरी अपडेट को ट्रैक करने के लिए अलग मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया सीएनएन ने बताया कि ईरान के लोग टेलीग्राम के जरिए एक-दूसरे के साथ मैसेजिंग या जानकारी साझा कर रहे हैं। इसके अलावा इंडोनेशियाई मीडिया आउटलेट ने बताया है कि ईरान के लोग एयरस्ट्राइक और अन्य जरूरी जानकारी के लिए माहसा अलर्ट ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएनए ने कहा बताया कि ईरान में हजारों लोग जरूरी जानकारी शेयर करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर लोग जानकारी साझा कर रहे हैं कि एयरस्ट्राइक कहां हुए, किन इलाकों

में बिजली चली गई और कितना नुकसान हुआ।

ईरान में होने वाले एयरस्ट्राइक के लिए कोई ऑफिशियल चेतावनी सिस्टम न होने के कारण, इसके नागरिक खुद ही समस्या का समाधान कर रहे हैं। ईरानी नागरिक अपना खुद का क्राउडसोर्स्ड एयर अटैक वॉर्निंग सिस्टम बनाते हैं। इंडोनेशया के डिजिटल मीडिया पोर्टल वीओआई के अनुसार, ईरान में जब मिलिट्री हमलों या मूवमेंट से जुड़ी पब्लिक वॉर्निंग देने के लिए कोई आधिकारिक सरकारी सिस्टम नहीं था, तब महसा अलर्ट नाम का प्लेटफॉर्म एक इमरजेंसी सॉल्यूशन के तौर पर सामने आया है।

ईरान के डिजिटल अधिकार कार्यकताओं और स्वयंसेवकों ने इस ऐप को तैयार किया है। यह ऐप हमलों और सैन्य गतिविधियों के स्थानों को मैप करने के लिए जनता, सोशल मीडिया और मैनुअल सत्यापन से प्राप्त डेटा पर आधारित है। ऑफिशियल मिलिट्री वॉर्निंग सिस्टम के उलट, महसा अलर्ट पूरी तरह से रियल-टाइम नहीं है। हालांकि, यह एप्लिकेशन हमलों या खतरों से जुड़ी वेरिफाइड जानकारी होने पर भी नोटिफिकेशन भेजता है।

हर डेटा अपडेट बहुत छोटा रखा जाता है, एवरेज सिर्फ 100केबी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कनेक्शन अनस्टेबल या लिमिटेड होने पर भी यूजर्स जानकारी हासिल कर सकें। इंडोनेशियाई न्यूज पोर्टल ने बताया कि सही जानकारी बनाए रखने के लिए, महसा अलर्ट के पीछे की टीम डेटा दिखाने से पहले अच्छी तरह वेरिफिकेशन करती है। पुष्टि के तौर पर मार्क की गई अटैक लोकेशन को सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो या इमेज-बेस्ड जांच से गुजरना होगा।

इसके अलावा, इस एप्लिकेशन में मेडिकल सुविधा पॉइंट, सीसीटीवी कैमरे और सरकार से जुड़े होने का शक वाले चेकपॉइंट जैसी अतिरिक्त जानकारी भी होती है।

अब तक, डेवलपमेंट टीम को 3,000 से ज्यादा आने वाली रिपोर्ट को वेरिफाई करना बाकी है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स के अनुसार, ईरान में इंटरनेट एक्सेस सामान्य स्तर के सिर्फ करीब 1 प्रतिशत तक रह गया है। इसका मतलब है कि अधिकांश लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और देश डिजिटल रूप से दुनिया से लगभग कट चुका है। 28 फरवरी, 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य हमलों की एक श्रृंखला के बाद से ही इंटरनेट ब्लैकआउट जैसी स्थिति है। (आईएएनएस)

होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो भी ट्रंप युद्ध खत्म करने को तैयार

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष रोकने के लिए हामी भरी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप सरकार के अधिकारियों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति ने अपने साथियों से कहा है कि वह ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध खत्म करने को तैयार हैं, भले ही होर्मुज स्ट्रेट काफी हद तक बंद रहे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप और उनके सहयोगियों का मानना है कि दुनिया के लिए जरूरी तेल सप्लाई वाले समुद्री रास्ते को खोलने की कोशिश से ईरान के साथ जंग लंबी खिंच सकती है। ट्रंप ने इस जंग को खत्म करने के लिए 4 से 6 हफ्ते का समय तय किया था, लेकिन इस मिशन की वजह से जंग इस समय से ज्यादा आगे बढ़ सकती है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने अधिकारियों के हवाले से बताया

कि ट्रंप ने फैसला किया कि अमेरिका को ईरान की नेवी और मिसाइल स्टॉक को कमजोर करने के अपने मुख्य मकसद को पाने पर ध्यान देना चाहिए। तेहरान पर स्ट्रेट के जरिए ट्रेड के फ्री फ्लो को फिर से शुरू करने के लिए डिप्लोमैटिक दबाव डालना चाहिए।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैसला लिया है कि अगर ये सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो व्हाइट हाउस यूरोपीय और गल्फ सहयोगियों पर इसे फिर से खोलने में आगे आने के लिए दबाव डालेगा। अधिकारियों ने आगे कहा कि सैन्य विकल्प अभी भी टेबल पर हैं, लेकिन वे राष्ट्रपि ट्रंप की तुरंत की प्राथमिकता नहीं हैं। हालांकि, इन आकलन के बावजूद, ईरान के साथ संघर्ष को लेकर ट्रंप का पब्लिक मैसेज एक जैसा नहीं रहा है। सोमवार सुबह, उन्होंने धमकी दी कि अगर जल्दी डील नहीं हुई तो वह ईरान के सभी इलेक्ट्रिक प्लांट, तेल के कुओं और खार्ग आइलैंड को पूरी तरह से खत्म कर देंगे।

इस बीच, सरकार ने इस इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। पिछले हफ्ते यूएसएस त्रिपोली और 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट इस इलाके में दाखिल हुई और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के कुछ हिस्से भी पहुंचने लगे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, 10,000 और जमीनी सैनिकों की तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है। ट्रंप ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर कब्जा करने के लिए एक मुश्किल मिशन के बारे में भी सोच रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सोमवार को कहा कि अमेरिका स्ट्रेट के जरिए नॉर्मल शिपिंग को फिर से शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है, हालांकि इसे फिर से खोलना सरकार के मुख्य सैन्य मकसदों में शामिल नहीं है। ट्रंप का मुख्य मकसद ईरान की नौसेना, मिसाइल प्रोग्राम, रक्षा उद्योग और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने पर केंद्रित है। (आईएएनएस)

द्विपक्षीय बैठक में भारत-रूस की आपसी संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 30 मार्च, 2026 को रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको के साथ विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) किया। विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ रणनीतिक साझेदारी, आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, बातचीत के दौरान, दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा किए।

दोनों पक्षों ने दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में हुए 23वें सालाना समिट में लिए गए फैसलों को लागू करने में हुई प्रक्रिया की समीक्षा की। दिसंबर की इस यात्रा के दौरान, रुडेंको ने भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात की। एफओसी का आखिरी राउंड मार्च 2025 में मॉस्को में हुआ था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, ₹भारत-रूस विदेश कार्यालय परामर्श सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश सचिव विक्रम मिसरी और रूस के उप विदेश मंत्री एंड्रे रुडेन्को ने की।

उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर आपसी दृष्टिकोण साझा किए। इसके अलावा, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मई में भारत आने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार, लावरोव 14-15 मई को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आ सकते हैं। इससे पहले 17 मार्च को, भारत और रूस ने नई दिल्ली में 7वां संयुक्त राष्ट्र परामर्श आयोजित किया, जिसमें चर्चा का मुख्य केंद्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के एजेंडे से जुड़े मुद्दे थे। विशेष रूप से आतंकवाद-रोधी उपाय, शांति स्थापना, यूएनएससी सुधार और अन्य विषय। (आईएएनएस)

बढ़ती कीमतों पर न्यूजीलैंड ने अपनों को दिया राहत पैकेज

वेलिंगटन। अमेरिका-ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर तेल की कीमतों पर साफ दिख रहा है। बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अपनी सरकार द्वारा दी जा रही लक्षित महंगाई राहत का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड वैश्विक ऊर्जा बाजारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, उनकी मदद करना जरूरी है। पीएम लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई की वजह से न्यूजीलैंड में पेट्रोल पंप पर कीमतें सीधे तौर पर बढ़ रही हैं। इससे पूरे देश में घरों और बिजनेस पर असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार सभी के लिए दबाव कम करने का जोखिम नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार को कोविड की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए, जहां ज्यादा खर्च से महंगाई और ज्यादा कर्ज हुआ था।

लक्सन ने कहा कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें समय पर सीमित अवधि के लिए और लक्षित सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सभी के लिए एक जैसे उपाय अपनाने से महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है। लक्सन सरकार ने इन-वर्क टैक्स क्रेडिट को कुछ समय के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे अप्रैल की शुरूआत से लगभग 143,000 कम और मिडिल-इनकम वाले काम करने वाले परिवारों को हर हफ्ते एक्स्ट्रा 50 डॉलर मिलेंगे, ताकि वे बढ़ते फ्यूल के खर्चों में मदद कर सकें। यह मदद एक साल तक या पेट्रोल की कीमतें कम होने तक चलेगी और इससे लगभग 14,000 और परिवारों को कम रेट पर उपलब्धता मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि इन-वर्क टैक्स क्रेडिट में बढ़ोतरी का मकसद महंगाई या कर्ज बढ़ाए बिना ज्यादा खर्चों के असर को कम करना है। इस बड़े पैकेज के तहत, न्यूजीलैंड के दस लाख से ज्यादा लोगों को मौजूदा सरकारी मदद पेमेंट में बढ़ोतरी मिलेगी।

लगभग 10 लाख पेंशनभोगी को बढ़ा हुआ न्यूजीलैंड पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसमें शादीशुदा जोड़े का हर दो हफ्ते का पेमेंट 50 डॉलर से ज्यादा बढ़ जाएगा। करीब 2.8 लाख परिवारों को बढ़े हुए फैमिली टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें सालाना 1,050 डॉलर तक अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। वहीं, छात्रों और लाभार्थियों को हर दो हफ्ते में लगभग 20 डॉलर ज्यादा दिए जाएंगे। सरकार ने 'वर्किंग फॉर फैमिलीज' योजना में बदलाव कर लगभग 1.4 लाख और परिवारों को समर्थन देने का कदम उठाया है। इसके साथ ही, लोगों को पहला घर खरीदने या रिटायरमेंट के लिए तेजी से बचत करने में मदद देने के लिए कीवीसेवर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। (आईएएनएस)

चीन ने अमेरिका और इजरायल से की शांति अपील

बीजिंग। चीन ने अमेरिका-इजरायल से ईरान के खिलाफ जारी आक्रमण को तुरंत रोकने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई बंद कर शांति बनाए रखने का अनुरोध करता है। इसके साथ ही चीन ने परमाणु संयंत्रों और 133 ऐतिहासिक स्थलों को पहुंचे नुकसान को भी अफसोसनाक बताया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में सरकार का पक्ष रखा।

उन्होंने कहा, ₹दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर पूरी इंसानियत के लिए एक बेशकीमती संपत्ति है। चीन को इस बात का बहुत अफसोस है कि संघर्ष के दौरान ईरान की सांस्कृतिक निशानियों और स्मारकों को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं चीन ने

परमाणु सुविधाओं पर हमलों का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे कदम बेहद खतरनाक हैं। बीजिंग ने कहा कि वह शांति बहाल करने के लिए अपनी ओर से कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगा। निंग ने कहा, ₹चीन अपील करता है कि यूएस-इजरायल तुरंत और पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई बंद करें, तुरंत संवाद शुरू करें, और इस संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करें जो हम मानते हैं कि कभी नहीं होना चाहिए था। ईरान पर यूएस-इजरायल की संयुक्त एयर स्ट्राइक से 28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष को 32 दिन हो गए हैं। इस दौरान दोनों ओर से हमले जारी हैं। यूएस-इजरायल की ओर से तेहरान और इस्फाहान पर भारी बमबारी जारी है, तो ईरान अपनी मिसाइलों से इजरायल के शहरों और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयर बेस, प्रतिष्ठानों आदि को निशाना बना रहा है। इस भयावह संघर्ष में ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई समेत कई शीर्ष नेता और सैन्य अधिकारी खो दिए हैं। इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर जल्द ही कोई डील नहीं हुई तो वे ईरान के मुख्य तेल एक्सपोर्ट हब और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे। (आईएएनएस)

यहूदी कमीडियन ने मेयर ममदानी की वजह से छोड़ा शो

न्यूयॉर्क। यहूदी कमीडियन मोर्दकै रोसेनफेल्ड ने सोमवार को कहा कि वह लोअर मैनहट्टन में होने वाले सालाना पासओवर-थीम वाले इवेंट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता चला है कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इसकी जानकारी दी। रोसेनफेल्ड को प्रोफेशनली 'मोडी' नाम से जाना जाता है। टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया कि यहूदी कमीडियन मोडी रोसेनफेल्ड को जब पता चला कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, तो वह पासओवर इवेंट से बाहर हो गए।

मेयर ममदानी मैनहट्टन में सिटी वाइनरी में आयोजित इवेंट में भाषण दे रहे हैं। वहीं कमीडियन मोडी इजरायली-अमेरिकी हैं, जो इस कार्यक्रम में अपना परफॉर्म करने वाले थे। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में मोडी ने कहा कि उन्हें आज तक नहीं बताया गया था कि ममदानी इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल, ममदानी इजरायल के नीतियों और फिलिस्तीन में हमास के खिलाफ नेतन्याहू सरकार की कार्रवाई के खिलाफ रहे हैं। वह इजरायल पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाने वाले बीडीएस (बहिष्कार, विनिवेश, प्रतिबंध) आंदोलन के समर्थक भी रहे हैं।

ममदानी ने अपने मेयर चुनाव कैंपेन के दौरान इजरायल विरोधी विचारों के लिए पहले से ही आलोचनाओं का

सामना कर रहे थे। इजरायल नेशनल न्यूज ने बताया कि उन्होंने मेयर बनने के बाद अपने ऑफिस के पहले दिन ही इजरायल से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द कर दिए, जो उनके पहले के एरिक एडम्स ने जारी किए थे। ममदानी ने जून 2025 के जिस ऑर्डर को रद्द किया उसमें इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस अलायंस (आईएचआरए) की एंटीसेमिटिज्म की वर्किंग डेफिनिशन को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी।

इसके साथ ही, उन्होंने एक अन्य आदेश को भी रद्द कर दिया है। इस आदेश के माध्यम से निर्वाचित मेयर्स और एजेंसी के कर्मचारियों पर इजरायल का बहिष्कार करने या वहां से निवेश वापस लेने (डिसइन्वेस्टमेंट) पर प्रतिबंध लगाया गया था। (आईएएनएस)

newG INDIA
News Beyond Noise

हम वह खबरची हैं, जो खबरों के साथ खबरों की भी खबर रखते हैं। हम NewG हैं, जहां खबर बिना शोरगुल के है। यहां news, without noise लिखी-कही जाती है।

विचार हममें भरपूर है, लेकिन विचारधारा से कोई खास इत्तेफाक नहीं। बात हम वही करते हैं, जो सही है। जो सत्य से परामुख है, वह हमें स्वीकार नहीं। यही हमारा अनुशासन है, साधन और साध्य भी। अंगद पांव इसी पर जमा रखे हैं। डिगना एकदम भी गवारा नहीं। ब्रीफ में यही हमारा about us है।

@newgindia
@newgindia
@newgindia
@newgindia

गाजा में मदद की कमी से लेबनान में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बढ़े हमले

संयुक्त राष्ट्र। मिडिल ईस्ट में संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकताओं ने लेबनान में स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमलों में तेजी से बढ़ोतरी और गाजा पट्टी में मानवीय कामों में बढ़ती रुकावटों की ओर इशारा किया। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा कि लेबनान में स्वास्थ्य सुविधाओं, एम्बुलेंस और मेडिकल कर्मचारियों पर हमले खतरनाक दर से बढ़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अकेले वीकेंड में सात घटनाओं की रिपोर्ट दी, जिसमें ड्यूटी पर तैनात कम से कम नौ स्वास्थ्यकर्मी मारे गए।

दक्षिणी लेबनान में ओसीएचए ने कहा कि हमलों में एम्बुलेंस को नुकसान हुआ, जिसमें नबातीह गवर्नरेट गवर्नोरेट के कफर सर शहर में हुए हमले में घायल हुए लोगों को ले जा रही गाड़ियां भी शामिल हैं। ओसीएचए ने कहा कि जब से तनाव बढ़ना शुरू हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर 87 हमले हुए हैं, जिसमें 52 स्वास्थ्यकर्मी मारे गए और 126 घायल हुए हैं। हफ्ते के अंत में जारी एक संयुक्त बयान में लेबनान के लिए यूएन के खास संयुक्त राष्ट्र के उप विशेष समन्वयक और मानवीय समन्वयक इमरान रिजा और लेबनान में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि

अब्दिनासिर अबुबकर ने स्वास्थ्यकर्मी और फर्स्ट रेस्पॉन्डर की सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि मेडिकल स्टाफ और सुविधाओं को कभी टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि वीकेंड में कम से कम 96 लोग मारे गए, जिससे तनाव बढ़ने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 1,238 हो गई, और 3,500 से ज्यादा घायल हुए।

ओसीएचए ने कहा कि बिगड़ते सुरक्षा हालात के बावजूद, ऑफिस और उसके पार्टनर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य साझेदार ने बेघर लोगों को 33,500 से ज्यादा मेडिकल सलाह दी है और 22,500 से ज्यादा लोगों को जरूरी दवाइयां पहुंचाई हैं। ओसीएचए ने कहा कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में, गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में आम लोगों पर जानलेवा हमले जारी हैं। मानवीय मदद के कामों पर पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं।

गाजा के रिहायशी इलाकों में हवाई हमले और गोलाबारी हुई। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ने सोमवार को कहा कि वे इजरायली हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस में एक अपील याचिका फाइल करने पर विचार कर रहे हैं। इस याचिका में इजरायल के नए एनजीओ रजिस्ट्रेशन सिस्टम को चुनौती दी जाएगी। उनका कहना है कि यह सिस्टम इजरायल और कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में उनके काम करने की काबिलियत को और कम करता है। ओसीएचए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एनजीओ मानवीय मदद में अहम भूमिका निभाते हैं, जो मिलकर इन इलाकों में हर साल लगभग 1 बिलियन डॉलर की मदद देते हैं। नई रजिस्ट्रेशन जरूरतें उन कई तरीकों में से हैं जो लोगों की मानवीय सेवाओं तक पहुंच को कमजोर कर रहे हैं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस ने इजरायली अधिकारियों से मानवीय राहत को तेजी से और बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में मदद करने, मानवीय कामों में रुकावट डालने वाली नीतियों को बदलने के लिए कहा है। इसके साथ ही ओसीएचए ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मानवीय संगठन मानवीय सिद्धांतों के हिसाब से काम कर सकें।

ओसीएचए ने कहा कि आम लोगों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए और कानून लागू करने के मामले में जानलेवा ताकत का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी तरीके से किया जाना चाहिए। गैरकानूनी हमले करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। (आईएएनएस)

प्रकाशक : नवनीत शरण, प्रकाशन स्थान : एसएफएस 334 प्रथम मंजिल, डा मुखर्जी नगर, दिल्ली 110009 द्वारा देशहित संदेश हिंदी समाचार पत्र को मुद्रक : देवानंद राय द्वारा मुद्राणलय (आरडी प्रिंटर एवं पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, बी-48, सेक्टर 8, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301) से मुद्रित।
दूरभाष 011-45710443, संपादक इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु प्रेस तथा नियतकालिक पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्यत विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। पंजीयन संख्या 64957 पंजीकरण तिथि 09/07/1996
E-mail:deshhitsandesh@gmail.com, R.N.I. No.-64957/1996
प्रधान संपादक : नवनीत शरण
रेजिडेंट एडिटर : संजय कुमार राय